लखनऊ

शनिवार, 1 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 333

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते।

TODAY WEATHER

DAY	NIGHT
32°	28°
Hi	Low

संक्षेप

बीजेपी के तेजतर्रार प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने छोड़ी पार्टी? बायो बदलकर राजनीति से संन्यास का दिया सीधा संकेत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खेमे से एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी सियासी हलचल सामने आई है। टीवी डिबेट्स में विरोधियों के पसीने छुड़ाने वाले बीजेपी के सबसे चर्चित और तेजतर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के पार्टी छोड़ने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पूनावाला ने बीजेपी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके हालिया कदम और बयानों ने इन अटकलों को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस पूरी सियासी हलचल की सुगबुगाहट तब शुरू हुई जब शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपना बायो अचानक बदल दिया। उन्होंने अपने प्रोफाइल से 'बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता' का पद हटा दिया है। पूनावाला ने गुरुवार को अपने इस नए अपडेटेड बायो का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने खुद को 'धर्म से इस्लाम, संस्कृति से हिंदू और विचारधारा से भारतीय' बताया है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन अनुयायी भी लिखा है। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि इस बड़े बदलाव के बावजूद उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अभी भी उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ही दर्शाया जा रहा है।

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 हुई, आठ जिलों में 2.12 लाख से अधिक लोग प्रभावित

गुवाहाटी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक आठ जिलों में 2.12 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस साल मरने वालों की कुल संख्या भी बढ़कर 80 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, गोलाघाट, शिवसागर, विश्वनाथ, चराइदेव, कामरूप (मेट्रो), जोरहाट, धेमाजी और नागांव जिलों में कुल 2,12,441 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस आपदा ने 21 राजस्व मंडलों (रेवेन्यू सर्कल) में 437 गांवों को प्रभावित किया है, जबकि बाढ़ के कारण 17,198 .09 हेक्टेयर फसल खराब हुई है। एएसडीएमए ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शिवसागर जिले में दो और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस सीजन में राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 80 हो गई है। अधिकारी प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं। विस्थापित परिवारों को आश्रय देने के लिए 21 जगहों पर राहत शिविर खोले गए हैं, जबकि जिला प्रशासन प्रभावित लोगों को भोजन, पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शहरी इलाकों में बाढ़ का असर कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के कुछ हिस्सों में बना हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि कई नदियों में जलस्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

लोकसभा में हंगामा, सरकार का आरोप- विपक्ष काम में बाधा डाल रहा है

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा ने शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए चर्चा में हिस्सा न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया कि वे कार्यवाही में बाधा डालने के बजाय बहस में भाग लें।

सदन में लगातार नारेबाजी के बीच दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा में बार-बार कामकाज में रुकावटें आईं। चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए TMC नेता डेरेक ओ'ब्रायन को फटकार लगाई और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पेश किए गए नियम 267 के तहत नोटिस को खारिज कर दिया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर सदन के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया। विरोध-प्रदर्शन जारी रहने के कारण कार्यवाही समय से पहले समाप्त कर दी गई और सदन को 3 अगस्त, 2026 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को भेष बदलकर संसद में आने वाले कुछ सांसदों को चेतावनी दी और कहा कि वे संसद की पवित्रता और मर्यादा को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने यह चेतावनी उस वक्त दी जब निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए 'पुजारी' की वेशभूषा में पहुंचे थे।

सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और आरोप लगाया कि मंत्री ने अपने बयान से सदन को गुमराह किया, जो विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का मामला बनता है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि वह केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करें।

खड़गे का पीएम नरेंद्र मोदी से तीखा सवाल : अगर शर्म है तो अमित शाह से इस्तीफा दिलवाइए

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि NEET पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन खत्म करने के बाद भी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करके और उन्हें हिरासत में लेकर सरकार उनसे बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने की मांग की। X पर एक पोस्ट में खड़गे ने आरोप लगाया कि BJP सरकारें अपने उस वादे से मुकर गई हैं जिसमें कहा गया था कि NEET पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन खत्म करने के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, 10 दिन पहले आपकी सरकार ने युवाओं पर लाठी, डंडे और पैलेट गन का इस्तेमाल करके कार्रवाई की थी। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च और देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का ज़िक्र किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि अब जब छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है, तो आप बदले की भावना से उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर रहे हैं और उन्हें ज़बरदस्ती हिरासत में ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं ने इस शर्त पर अपना आंदोलन वापस लिया था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी; अब आपकी सरकारें अपनी ही बात से मुकर गई हैं। खड़गे ने यह भी दावा किया कि युवा प्रदर्शनकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे थे और युवा महिलाओं को डॉक्स (उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक) किया जा रहा था। सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर संसद में कोई बात नहीं की। खड़गे ने कहा कि यह कैसा 'अहंकार' है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन में आए तक नहीं और जवाबदेही पर बयान देने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि अपनी इज़्ज़त बचाने और अपनी छवि को सुरक्षित रखने के ये तरीके अब काम नहीं आएंगे; युवाओं को आपकी असलियत पता चल गई है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि अगर ज़रा भी शर्म बची है, तो अमित शाह से इस्तीफ़ा

संसद में अचानक 'साधु' बनकर पहुंचे पप्पू यादव, राहुल गांधी से भी ले लिया चंदा

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के संसद भवन परिसर में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया, जब एक जाने-माने राजनेता अचानक सिर से पैर तक भगवा चोला पहनकर 'साधु के भेष में वहां पहुंच गए। यह कोई आम साधु नहीं, बल्कि बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव थे। हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले पप्पू यादव ने इस बार विरोध प्रदर्शन का ऐसा अनोखा और नाटकीय तरीका चुना, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उनका यह पूरा प्रदर्शन अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित हेराफेरी के गंभीर आरोपों को लेकर था, जिस पर अब सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर चंदे में कथित घोटाले और अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए पप्पू यादव पूरी तरह से संन्यासी के भेष में संसद भवन पहुंचे थे। विरोध जताते

'जेन जी को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर Gen Z को डराने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'PM मोदी और अमित शाह, आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ीं। अब आप FIR दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसे लेकर सावधान रहें।' उल्लेखनीय है कि नीट-पेपर लीक में हुई गड़बड़ियों के विरोध में हाल ही में देश भर के युवाओं (Gen-Z) ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। 20 जुलाई को जब जंतर-मंतर पर धरना दे रहे छात्र जब जंतर-मंतर की ओर कूच किए तो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। राहुल गांधी छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुई इसी कार्रवाई पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली एक स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय समिति बनाने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, "छात्र न्याय के हकदार हैं।

राहुल गांधी के बेतुके बयान देने का इतिहास : निशिकांत दुबे ने प्रिविलेज मोशन का किया समर्थन

नई दिल्ली, एजेंसी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को राहुल गांधी के कथित असंसदीय बयानों को लेकर उनके खिलाफ अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गांधी लंबे समय से बेबुनियाद और बेतुके बयान देते रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सदस्य अपना आपा खो बैठे हैं क्योंकि पार्टी बारह साल से सत्ता से बाहर है; उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार प्रस्ताव उसी सोच का नतीजा है। दुबे ने कहा कि वे बेबुनियाद और बेतुकी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, और यह आदत उनमें लंबे समय से है। हालांकि, उनकी मौजूदा सोच की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी बारह साल से सत्ता से बाहर है। सत्ता के बिना, कांग्रेस के सदस्य अपना आपा खोते हुए दिखते हैं। यह विशेषाधिकार प्रस्ताव उसी सोच का नतीजा है। मैं लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई करने की अपील करता हूं। जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, तब से कम से कम पंद्रह विशेषाधिकार प्रस्ताव लंबित हैं। मैं विनम्रतापूर्वक स्पीकर से अनुरोध करता हूं कि वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और इन मामलों पर कार्रवाई करें।

'अपशब्दों पर एफआईआर निंदनीय', सीजेपी के सौरव दास का सवाल : सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं?

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने से अपनी पार्टी को अलग कर लिया। साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल किए जाने को बेहद निंदनीय बताया। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर नोएडा की एक लड़की के खिलाफ FIR दर्ज होने पर, कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों के इस्तेमाल की निंदा की जा सकती है। लेकिन, पुलिस के ज़रिए उन्हें निशाना बनाने और परेशान करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दास ने कहा कि इस देश में अपशब्दों का इस्तेमाल करना कब से आपराधिक अपराध हो गया? लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लोकसभा के 50% सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप बस उन्हें अलग-थलग करके एक मिसाल बनाना चाहते हैं। यह पूरी तरह से निंदनीय है। मैं एक बार फिर सरकार और उसकी पुलिस व्यवस्था से अपील करता हूं कि वे युवाओं को परेशान करना बंद करें। इस तरह से युवाओं को निशाना बनाना बंद करें और इस लड़की को छोड़ दें। ऐसे मामलों में पुलिस बल का इस तरह का दुरुपयोग बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सौरव दास ने युवा पीढ़ी से अपील की कि वे शब्दों के चुनाव में सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि मैं युवा पीढ़ी से गुज़ारिश करूंगा कि वे अपने शब्दों और आम लोगों के ख़िलाफ़ की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर बहुत सावधान रहें। हालांकि, उन्होंने फिर से कहा कि प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पुलिस से भी कहेंगे कि वे शांत रहें और किसी भी राजनीतिक मकसद के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करें।

हेलिकॉप्टर अब बनेंगे ड्रोन हंटर, एआई रडार और माइक्रो-मिसाइल से होंगे लैस

नई दिल्ली, एजेंसी। ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन से बढ़ते खतरे के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने हेलिकॉप्टरों को भी एयरबोर्न काउंटर-ड्रोन प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, इसके तहत हेलिकॉप्टरों पर एआई आधारित रडार, माइक्रो-मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और जैमिंग पॉड्स लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। IAF का मकसद ऐसे हेलिकॉप्टर तैयार करना है जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन को हवा में ही detect और destroy कर सकें।

इसके लिए हेलिकॉप्टरों पर AI-powered रडार लगाए जाने की योजना है। ये रडार छोटे और कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोन को पहचानने और ट्रैक करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही हेलिकॉप्टरों को माइक्रो-मिसाइल और 20mm फ्रंट गन से लैस करने की जरूरत बताई गई है। इन हथियारों का इस्तेमाल धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन और दूसरे छोटे हवाई खतरों को मार गिराने के लिए किया जा सकेगा। सिर्फ मिसाइल और गन ही नहीं, बल्कि हेलिकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इनमें हल्के RF और GPS जैमर शामिल होंगे, जो दुश्मन के ड्रोन के कम्युनिकेशन और नेविगेशन को बाधित कर सकेंगे। इन सिस्टम को Electro-Optical और Infrared सेंसर पॉड्स के साथ जोड़ने की योजना है। इससे दिन और रात दोनों समय छोटे ड्रोन की पहचान और निगरानी की क्षमता बढ़ेगी।

25 मीटर तक के एयर-बर्स्ट की क्षमता

माइक्रो-मिसाइलों के लिए ऐसे वॉरहेड की जरूरत बताई गई है, जिनमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज या टाइम-डिले फ्यूज का इस्तेमाल हो। इनका मकसद लक्ष्य के बेहद करीब हवा में विस्फोट कर ड्रोन को नष्ट करना है। करीब 25 मीटर के मिड-एयर बर्स्ट रेडियस में फ्रैगमेंटेशन प्रभाव पैदा करने वाले वॉरहेड की जरूरत पर जोर दिया गया है।

रूस-यूक्रेन जंग : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- मारे गए और लापता भारतीयों के परिवारों की मदद करे केंद्र

नई दिल्ली, एजेंसी। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान नौकरी का झांसा देकर रूस भेजे गए और बाद में युद्ध के मोर्चे पर पहुंचा दिए गए भारतीय नागरिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विदेश मंत्रालय तुरंत एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो युद्ध में मारे गए, घायल हुए या अब भी लापता भारतीयों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे और उन्हें हर जरूरी जानकारी व सहायता उपलब्ध कराए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि पीड़ित परिवार पहले ही भारी मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें समय पर सही जानकारी और हर संभव मदद मिले।

सुप्रीम कोर्ट के पांच बड़े निर्देश

विदेश मंत्रालय में एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो पीड़ित परिवारों से सीधे संपर्क में रहेगा।

युद्ध में मारे गए भारतीयों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल का मिलान कराया जाएगा।

नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के समक्ष मुआवजा क्लेम दाखिल कराने में विदेश मंत्रालय परिवारों की मदद करेगा।

पीड़ित परिवारों को सभी जरूरी जानकारी और प्रक्रियाएं उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता देंगे।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला उन भारतीय युवाओं से जुड़ा है, जिन्हें ट्रैवल एजेंटों ने रूस में अच्छी नौकरी का लालच देकर भेजा था। परिवारों का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद कई युवाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ रूस-यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इस दौरान कई भारतीयों की मौत हो गई, कुछ घायल हुए और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इन्हीं परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार से अपील की थी कि उनके परिजनों का पता लगाया जाए, मृतकों के पार्थिव शरीर भारत लाए जाएं और रूसी सरकार से उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

पीड़ित परिवारों को कैसे मिलेगी मदद?

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे पीड़ित परिवारों की हर कानूनी प्रक्रिया में मदद करें। इसमें मुआवजा क्लेम दाखिल करना, जरूरी दस्तावेज तैयार करना, कागजी कार्रवाई पूरी कराना और पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी से जुड़ी औपचारिकताओं में सहायता शामिल है।

मायावती ने Yogi सरकार को कहा Thank You, समाजवादी पार्टी को घेरा

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (SP) पर संकीर्ण जातिवादी सोच रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि SP ने उत्तर प्रदेश में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान दलित और OBC महापुरुषों के नाम पर रखे गए कई जिलों के नाम बदल दिए थे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने 'संत रविदास नगर' (भदोही) का नाम बहाल करने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का आभार जताया और कांशीराम नगर (कासगंज) सहित अन्य पुराने नामों को भी बहाल करने की अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि SP सरकार ने दुर्भावना और संकीर्ण राजनीतिक मकसद से काम करते हुए BSP शासन के दौरान लिए गए नामकरण के फैसलों को बदला था। मायावती ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों से सभी जानते हैं कि मौजूदा UP सरकार ने 'संत रविदास नगर' जिले का दर्जा बहाल कर दिया है। इस जिले को मूल रूप से BSP सरकार ने भदोही को जिला मुख्यालय का दर्जा देकर बनाया था। बाद में समाजवादी पार्टी (SP) सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी सोच के कारण इसका नाम बदल दिया था, और अब इसे फिर से 'संत रविदास नगर' जिले के रूप में बहाल कर दिया गया है। पार्टी इस बहाली के लिए राज्य सरकार की आभारी है। BSP प्रमुख ने बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चार कार्यकाल के दौरान, उन्होंने प्रशासन को बेहतर बनाने और दलित व OBC समुदायों में जन्मे महान संतों और गुरुओं का सम्मान करने के लिए संत रविदास नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर और भीम नगर जैसे ज़िले बनाए थे।

प्रयागराज में यमुना पर बनेगा नया फोर लेन पुल, बढ़ेगी MP व छत्तीसगढ़-झारखंड की कनेक्टिविटी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। संगम नगरी में बढ़ते यातायात के दबाव और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यमुना नदी पर एक और फोर लेन पुल बनेगा। इसके निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। सेतु निगम की ओर से तैयार की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नए और पुराने यमुना पुल के बीच लगभग 3,200 मीटर लंबा आधुनिक फोर लेन पुल बनाया जाएगा।

यमुना पुल पर जाम की स्थित नहीं रहेगी

इसके निर्माण से न केवल प्रयागराज शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। प्रस्तावित पुल के बनने के बाद प्रयागराज से चित्रकूट, मीरजापुर और विंध्य क्षेत्र की ओर यात्रा पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। वर्तमान में यमुना पुल पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण कई बार जाम की स्थिति बन जाती है।

मंजूरी के बाद डीपीआर तैयार होगा

सेतु निगम की ओर से मई में पुल बनाने का प्रस्ताव शासन के पास भेज दिया गया है। निगम की ओर से परियोजना का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है। योजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। पुल के निर्माण से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होने के साथ व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे प्रयागराज की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने में यह पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नए व पुराने यमुना पुल के बीच बनेगा फोन लेन ब्रिज

सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक रोहित मिश्र ने बताया कि आवागमन सुगम बनाने के लिए नैनी की ओर यमुना नदी पर बने नए और पुराने पुल के बीच में फोर लेन पुल का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद कार्य तेजी से कराया जाएगा।

पैमाइश के दौरान खूनी संघर्ष, रास्ते का विवाद बना रणक्षेत्र

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय, सुल्तानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के मऊ गांव में वर्षों से चले आ रहे आबादी की जमीन के रास्ते के विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया, जब बृहस्पतिवार देर शाम न्यायालय के आदेश पर कमीशन द्वारा पैमाइश की जा रही थी। पैमाइश के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते कहासुनी लाठी-डंडों, ईंट-पत्थरों से खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अमर बहादुर मिश्र और राजेश कुमार मिश्र पक्ष के बीच पहले रास्ते को लेकर तीखी बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में दोनों ओर से लोग आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई। संघर्ष इतना उग्र था कि कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े।

सूचना मिलते ही बल्दीराय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बल्दीराय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल चार लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में एक पक्ष से समन मिश्रा (20), अनुज मिश्रा (17), अनुभव मिश्रा (15) और राजकुमार (28) घायल हुए हैं। दूसरे पक्ष से अंकित कुमार (22), कुसुम (36), राम शिरोमणि मिश्रा (53), संतोष कुमार (46), राहुल मिश्रा (18), फूलगेंदा मिश्रा (60), राम लली (60), समर बहादुर (67) और प्रिया मिश्रा (15) घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार, रास्ते का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट के आदेश पर कमीशन द्वारा पैमाइश कराई जा रही थी। इसी दौरान विवाद बढ़ने से हिंसक झड़प हो गई।

क्षेत्राधिकारी बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यह घटना एक बार फिर बताती है कि भूमि और रास्ते से जुड़े विवाद यदि समय रहते नहीं सुलझाए जाएं तो वे कभी भी गंभीर कानून-व्यवस्था की चुनौती बन सकते हैं।

मौत को दावत देता शारदा नहर मार्ग, विभाग ने शुरू कराया सफाई अभियान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बल्दीराय/सुल्तानपुर। 27 जुलाई को प्रकाशित #मौत को दावत देता शारदा नहर मार्ग# शीर्षक समाचार का असर दिखाई देने लगा है। खबर को संज्ञान में लेते हुए सिंचाई विभाग ने 31 जुलाई की सुबह से हरौरा बाजार से एस. चंद्रा विद्यालय मोड़ तक शारदा नहर की पटरी पर उगी झाड़-झंखाड़ की कटाई का कार्य शुरू करा दिया। वर्षों से सड़क किनारे फैली घनी झाड़ियां राहगीरों, स्कूली छात्रों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बनी हुई थीं। कई स्थानों पर दृश्यता बाधित होने से आमने-सामने वाहन आने पर हादसे की आशंका बनी रहती थी।

स्थानीय लोगों ने समाचार प्रकाशित होने के बाद विभागीय कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नियमित रूप से सफाई और रखरखाव कराया जाए तो यह मार्ग पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित हो जाएगा।

इस संबंध में अवर अभियंता (JE) पवन पाल ने बताया कि बल्दीराय जाने वाली शारदा नहर पटरी के किनारे उगी झाड़ियों को हटाने का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही पूरी नहर पटरी को झाड़ियों से अतिक्रमणमुक्त कर सुरक्षित आवागमन के योग्य बनाया जाएगा।

यह कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाली जिम्मेदार पत्रकारिता प्रशासन को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हरदोई में प्रेमी युगल का सुसाइड : 1 KM की दूरी पर पेड़ से लटकते मिले शव, 15 साल पहले हुई थी महिला की शादी

आर्यावर्त संवाददाता

हरदोई। अरवल के हैदराबाद मजरा उमरौली जैतपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक प्रेमी युगल ने एक किलोमीटर के दायरे में दो अलग-अलग पेड़ों से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया और गांव में सनसनी फैल गई।

अरवल के ग्राम हैदराबाद मजरा उमरौली जैतपुर के जनवेश राजस्थान में मजदूरी करता था। उसका गांव की ही एक विवाहिता से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात लगभग 8:30 बजे महिला का देवर जनवेश के घर शिकायत करने पहुंचा था।

गुस्से में जनवेश अपने घर से निकला था

इस बात से नाराज होकर जनवेश गुस्से में घर से कुसुम खोर गंगापुल की ओर निकल गया। देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटा, तो स्वजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह जब किसान खेतों में फसल देखने गए, तो उन्होंने जनवेश का शव जामुन के पेड़ पर चारपाई के बान से लटकता देखा। उसकी चप्पलें पेड़ के नीचे रखी थीं और जेब में मोबाइल मौजूद था।

कुछ ही दूरी पर विवाहिता का मिला शव

अभी गांव वाले इस हादसे से उबर भी नहीं पाए थे कि पता चला कि कुछ ही दूरी पर महिला का शव भी गूलर के पेड़ पर साड़ी के फंदे से लटका हुआ है। सूचना मिलते ही दोनों परिवारों के लोग रोते-बिलखते मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया।

15 साल पहले हुआ था महिला का विवाह

महिला की शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी और उसका मायका गांव में ही है। वहीं मृतक जनवेश अविवाहित था और तीन भाइयों व एक बहन में तीसरे नंबर पर था। घटना की सूचना पर उपनिरीक्षक शिवकुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

चुनाव में मंडी हटाने पर अमहट के व्यापारियों में रोष, कोर्ट जाने की चेतावनी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अमहट फल मंडी के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम के नेतृत्व में मंगलवार को फल मंडी महामंत्री कार्यालय पर व्यापारियों और पदाधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में मंडी की समस्याओं के साथ सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के समय व्यापारियों को मंडी से बाहर कर दिया जाना रहा। व्यापारियों का कहना है कि हर चुनाव में प्रशासन द्वारा मंडी शिफ्ट कर दिए जाने से कारोबार ठप हो जाता है और ग्राहकों को भी परेशानी होती है। अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने कहा हर चुनाव में मंडी हटाकर व्यापार चौपट कर दिया जाता है। यह वर्षों से चली आ रही समस्या है। अब इसका स्थायी समाधान जरूरी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बार चुनाव से पहले जिला प्रशासन से वार्ता कर ऐसी व्यवस्था कराई जाएगी जिससे व्यापारियों को मंडी से बाहर न किया जाए। व्यापारियों ने साफ कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे मजबूरन कोर्ट का सहारा लेंगे।

टेंडर पर ताला, सवालों का तूफान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह विकास नहीं बल्कि विकास कार्यों के टेंडरों को लेकर उठे गंभीर सवाल हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों का आरोप है कि नगर पालिका में पारदर्शिता की जगह मनमानी हावी है और टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित रखकर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

मई और जून में जारी कई विकास कार्यों की निविदाओं की अंतिम तिथि बीत चुकी है। नियमों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय निविदाएं समय पर खोली जानी चाहिए थीं लेकिन आरोप है कि आज तक कई टेंडरों के लिफाफे नहीं खोले गए। सवाल उठ रहा है कि आखिर नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ? क्या किसी विशेष ठेकेदार के लिए पूरी प्रक्रिया रोक दी गई?

नगर पालिका क्षेत्र में यह चर्चा भी जोरों पर है कि कई विकास कार्य पहले ही करा दिए जाते हैं और बाद में टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाती है। यदि यह सही है तो यह न सिर्फ वित्तीय नियमों पर सवाल है। बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने में निर्माण शाखा के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। चर्चा है कि पूरी प्रक्रिया को इस तरह संचालित किया जा रहा है जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो और कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ मिले। यदि ये आरोप निराधार हैं तो नगर पालिका को पूरी टेंडर प्रक्रिया सार्वजनिक करने में हिचक क्यों है।

ईओ से संपर्क नहीं हो सका

इन आरोपों पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

बंद कमरे की बैठक पर भी चर्चाएं

सूत्रों के अनुसार हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ बंद कमरे में हुई बैठक को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे सवाल और गहरे हो गए हैं। आखिर समय बीतने के बाद भी टेंडरों के लिफाफे क्यों नहीं खोले गए? क्या नगर पालिका सभी लंबित टेंडरों की स्थिति सार्वजनिक करेगी? क्या पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होगी। यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो पारदर्शिता दिखाने में देरी क्यों। सरकारी टेंडर कोई बंद तिजोरी नहीं, बल्कि जनता के पैसे का हिसाब है। जितनी देर लिफाफे बंद रहेंगे, उतने ही सवाल उठेंगे। अब निगाहें प्रशासन पर हैं। क्या जवाब मिलेगा या फिर चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बनेगी।

विश्व ओआरएस दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी आयोजित

रैली निकालकर छात्राओं ने डायरिया के प्रति किया जागरूक

» दो से तीन बार पतली दस्त हो तो बच्चों को दें ओआरएस : एसीएमओ

आर्यावर्त संवाददाता

फर्रुखाबाद। स्थानीय रामानंद बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शुक्रवार को जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को डायरिया के कारण, बचाव और उपचार सम्बन्धी जरूरी संदेश दिए। इसके साथ ही विश्व ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जागरूकता गोष्ठी भी आयोजित की गयी।

पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के तहत आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव ने कहा कि डायरिया से डरने नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका उपचार पूरी तरह संभव है। बच्चे को दिन में दो-तीन बार पतली दस्त हो तो ओआरएस का घोल और जिंक जरूर दें, क्योंकि यही इसका सही उपचार है। एसीएमओ ने कहा कि "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शून्य से पांच साल तक के बच्चों की डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना और दस्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके लिए समुदाय में डायरिया के प्रति जनजागरूकता को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। एसीएमओ ने कहा कि ओआरएस और जिंक सभी स्वास्थ्य इकाइयों और आशा कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध है, अगर बच्चे को डायरिया की शिकायत है तो इन जगहों से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

गोष्ठी में पीएसआई इंडिया के अमरीश ने स्टॉप डायरिया कैंपेन के दौरान जिले में आयोजित की जा रहीं गतिविधियों, जैसे- प्रचार वाहनों का संचालन, स्कूलों में आयोजित की जा रहीं गतिविधियों के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा संचालित कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों के माध्यम से भी डायरिया से संबंधित जागरूकता संदेशों का प्रसारण कर कैंपेन में सहयोग किया जा रहा है।

बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) कंचन बाला, डीसीपीएम रणविजय प्रताप सिंह, शहरी स्वास्थ्य समन्वयक राजीव पाठक, डॉ. विवेक सक्सेना, डॉ. शोभा सक्सेना, रामानंद बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या रीता दुबे, अध्यापिका फराना, पीएसआई इंडिया से अनुपम मिश्र आदि उपस्थित रहे।

यूपी को नए एक्सप्रेसवे की सौगात: जल्द शुरू होगा काम, तीन राज्यों से गुजरेगा, आसमान छुएंगे जमीनों के भाव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। एक्सप्रेसवे के लिए जिले में करीब 14 किलोमीटर लंबी भूमि का अधिग्रहण होना है। पूर्व में किसानों का मुआवजा 144 करोड़ रुपये तय किया गया था। इस राशि से असंतुष्ट किसानों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को जमीन पर कब्जा नहीं लेने दिया था। मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने 148 वाद दायर किए थे। इनमें से 80 से अधिक वादों का मध्यस्थता के जरिए निस्तारण कर लिया गया है। अब किसानों को 50 करोड़ रुपये अधिक यानी कुल 195 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जाएगा। इस फैसले के साथ ही एक्सप्रेसवे के निर्माण में लंबे समय से चली आ रही बड़ी अड़चन दूर हो गई है।

4,613 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे

आगरा के देवरी गांव से शुरू होकर ग्वालियर के सुसेरा गांव तक जाने वाले इस एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (एनएच-719डी) का निर्माण बीओटी (टोल) मोड पर किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 4,613 करोड़ रुपये है। एनएचएआई ने इसके निर्माण के लिए मेसर्स जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ 20 साल का रियायत समझौता (कन्सेशन एग्रीमेंट) किया है, जिसमें 30 महीने की निर्माण अवधि भी शामिल है। जनवरी में कार्यदायी संस्था को निर्माण शुरू करना था, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं मिलने से प्रोजेक्ट करीब सात महीने पिछड़ चुका है।

तीन राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे, घटेगी दूरी

यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर गुजरेगा। इसके बनने से आगरा, धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर के बीच हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे न सिर्फ यात्रा का समय बचेगा, बल्कि एनएच-44 के मौजूदा आगरा-ग्वालियर रूट पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

चंबल में घड़ियालों की सुरक्षा का भी रखा ध्यान

यह परियोजना राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरेगी। चंबल नदी में घड़ियालों के संरक्षण के लिए नदी पर एक विशेष केबल स्टे ब्रिज बनाया जाएगा, जिस पर ध्वनि अवरोधक और लाइट कटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे एक्सप्रेसवे पर आठ बड़े पुल, 23 छोटे पुल, छह फ्लाईओवर, एक रेलवे ओवरब्रिज और 192 पुलिया बनाई जाएंगी।

किसानों को 50 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे

एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह ने बताया कि मध्यस्थता वाद में सहमति बन गई है। प्रभावित किसानों की पूर्व निर्धारित मुआवजा राशि को बढ़ाया है। करीब 50 करोड़ रुपए किसानों को अब अधिक मिलेंगे। भुगतान के लिए प्रस्ताव एनएचएआई को भेजा जा रहा है।

पांच एक्सप्रेसवे का शहर हो जाएगा आगरा

आगरा देश का पहला शहर हो जाएगा, जहां पांच एक्सप्रेसवे निकलेंगे। फिलहाल दो एक्सप्रेसवे आगरा से शुरू हो रहे हैं। इनमें आगरा से नोएडा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा से लखनऊ के बीच आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं। तीन एक्सप्रेसवे आगरा से प्रस्तावित हैं, जिनके लिए प्रक्रिया जारी है। इनमें आगरा-बरेली एक्सप्रेसवे, आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे, आगरा-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे शामिल है। डेढ़ से दो साल के अंदर इन एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

वाराणसी से अयोध्या जा रही क्रूज़र का टायर फटा, बिजली के पोल से टकराई

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जनपद के लंभुआ क्षेत्र में शुक्रवार तड़के वाराणसी से अयोध्या जा रही एक क्रूजर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा सुबह करीब 5:15 बजे उस समय हुआ, जब वाहन का पिछला टायर अचानक फट गया। टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गया।

अपर पुलिस अधीक्षक वृज नारायण सिंह के अनुसार, क्रूजर में मध्य प्रदेश के शिवढ़ी निवासी लगभग 15 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस टीम भी तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस के अनुसार घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सभी घायलों का उपचार जारी है। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सामान्य है तथा मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

किसानों और मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री ने कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के दिए निर्देश, मंडी परिषद का 3025 करोड़ का बजट मंजूर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को और मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मेधावी बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश की मंडियों के आधुनिकीकरण, कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करने और किसान कल्याण से जुड़े अनेक प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के 3025.49 करोड़ के बजट सहित किसान कल्याण और मंडी व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी मंडियों का आधुनिकीकरण कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि किसानों को पारदर्शी, सुगम और बेहतर विपणन व्यवस्था उपलब्ध हो सके। उन्होंने मंडियों में पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया।मुख्यमंत्री ने मंडी परिसरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत कृषि उपज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए नियमों को अधिक व्यवहारिक और निवेश अनुकूल बनाया जाए, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिले, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हों।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से किसानों की भागीदारी बढ़ाने तथा प्रत्येक जनपद में जैविक उत्पादों के प्रमाणन की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाएगी।संचालक मंडल ने वर्ष 2025-26 के संशोधित आय-व्यय अनुमान और वर्ष 2026-27 के बजट को भी मंजूरी दी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 2228.59 करोड़ की अनुमानित आय तथा 3025.49 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है। बैठक में बताया गया कि मंडी समितियों की आय वर्ष 2024-25 में 1991.33 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 2305.80 करोड़ हो गई है, जो 15.79 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।बजट में मंडी स्थलों के निर्माण एवं विस्तार, संपर्क मार्गों के निर्माण और मरम्मत, ग्रामीण हाट, किसान बाजार, गोवंश आश्रय स्थल, छात्रावास निर्माण, मंडी समितियों के लिए भूमि क्रय तथा अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। पूर्व से स्वीकृत निर्माण कार्यों को गति देने के लिए 1212.02 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है।बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2030 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन दोनों योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे दुर्घटना या खेत-खलिहान में आग लगने जैसी परिस्थितियों में किसानों और उनके परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहे।इसके अलावा मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन एवं तिलहन की खरीद व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं को ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।बैठक में परिषद के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान हित से जुड़े सभी विकास कार्यों को तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाती रहेगी।

महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। कृष्णानगर थाना पुलिस ने महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण करने तथा धमकी देने के आरोप में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से मृतका के संपर्क में था और दोनों के बीच शादी तथा आर्थिक सहायता को लेकर लगातार विवाद होता था। घटना के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपता फिर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।पुलिस आयुक्त तरुण गाबा और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार के निर्देश पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार 30 जुलाई को आशियाना क्षेत्र निवासी आकांक्षा गुप्ता की तहरीर पर कृष्णानगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनकी बहन का आरोपी वरुण श्रीवास्तव से लंबे समय से परिचय था। इस दौरान आरोपी ने मृतका का शारीरिक और आर्थिक शोषण किया तथा विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इन परिस्थितियों से आहत होकर महिला ने 29 जुलाई को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की और शुक्रवार को एलडीए-2 स्थित माता जी की बगिया क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका मृतका से काफी समय से परिचय था और दोनों के बीच निकट संबंध थे। समय के साथ दोनों के बीच शादी और आर्थिक मदद को लेकर विवाद बढ़ने लगा था। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन भी दोनों के बीच बातचीत के दौरान विवाद हुआ, जिसमें आरोपी ने मृतका के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसे धमकी दी। इसके बाद महिला ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था।

जेल की दीवार फांदकर फरार हुआ पॉक्सो आरोपी, जिला कारागार की सुरक्षा पर उठे सवाल

लखनऊ। गोरखपुर जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था उस समय कटघरे में आ गई, जब दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप में निरुद्ध एक बंदी शुक्रवार सुबह जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फरार बंदी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, जबकि सुरक्षा में हुई चूक की भी जांच शुरू कर दी गई है।जानकारी के अनुसार, बांसगांव क्षेत्र के सरसोपार निवासी विपिन पुत्र हरिशंकर को दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के एक मामले में 18 जुलाई को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया था। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे जेलकर्मी 49 बंदियों को जेल परिसर से सटी नई बाउंड्री वाल के पास स्थित बगिया में कार्य कराने के लिए लेकर गए थे।इसी दौरान विपिन ने मौका पाकर पहले परिसर में मौजूद एक पेड़ पर चढ़ाई की और फिर बाउंड्री वाल फांदकर फरार हो गया।

ऑपरेशन मुस्कान की बड़ी सफलता : नौ महीने बाद सकुशल मिला लापता दिव्यांग बालक

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी) थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत सराहनीय सफलता हासिल करते हुए करीब नौ महीने पहले लापता हुए 14 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों से मिला दिया। लंबे समय तक चले सत्यापन, अभिलेखों के मिलान और लगातार पुलिस प्रयासों के बाद बालक की पहचान संभव हो सकी।यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त तरुण गाबा, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था बबलू कुमार के निर्देशन में अपराधियों एवं गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव तथा सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के पर्यवेक्षण में एएचटी थाना पुलिस ने इस मामले का सफल अनावरण किया।पुलिस के अनुसार मड़ियांव क्षेत्र निवासी नीतू सिंह ने 9 नवंबर 2025 को अपने 14 वर्षीय पुत्र उज्ज्वल सिंह के 6 नवंबर 2025 से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रारंभिक विवेचना मड़ियांव थाने में हुई, लेकिन बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी) थाने को सौंप दी गई।जांच के दौरान पता चला कि बालक के लापता होने के अगले ही दिन 7 नवंबर 2025 को बीकेटी थाना पुलिस को वह लावारिस अवस्था में मिला था। मानसिक रूप से दिव्यांग होने के कारण वह अपना नाम, पता या परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। इसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के आदेश पर मोहन रोड स्थित राजकीय बाल गृह (शेल्टर होम) भेज दिया, जहां उसकी पहचान न होने के कारण उसे अज्ञात बालक के रूप में रखा गया।

उधर एएचटी थाना पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार विभिन्न जिलों, आश्रय गृहों और अन्य संभावित स्थानों पर गुमशुदा बच्चों का सत्यापन कर रही थी। 27 जुलाई 2026 को मोहन रोड स्थित राजकीय बाल गृह में उपलब्ध अभिलेखों और गुमशुदा बच्चों के फोटोग्राफ का मिलान किया गया, जिसमें बालक की पहचान उज्ज्वल सिंह के रूप में हुई। इसके बाद उसके परिजनों को बुलाकर पहचान कराई गई।

केयरटेकरों के मानदेय भुगतान में देरी पर डिप्टी सीएम सख्त

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी सामुदायिक शौचालयों में कार्यरत केयरटेकरों के मानदेय भुगतान में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर मांगों पर निर्णय लिया जाएगा।रवीन्द्रालय में राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस पर आयोजित जनकल्याण केयरटेकर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मिलने वाला 6 हजार रुपये का मानदेय बेहद कम है और उसमें भी भुगतान में देरी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार मानदेय बढ़ाने और राशि सीधे केयरटेकरों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करेगी।महासम्मेलन के संयोजक विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि अधिकांश केयरटेकर महिलाएं हैं और उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। उन्होंने भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाकर सीधे बैंक खातों में धनराशि भेजने की मांग उठाई।मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने संगठन का मांगपत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और समस्याओं के समाधान का प्रयास करने का भरोसा दिया। वहीं भाजपा प्रदेश मंत्री डॉ. राहुल वाल्मीकि ने भी केयरटेकरों की समस्याओं को पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखने तथा उन्हें पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मंच से उतरकर महिला केयरटेकरों के बीच जमीन पर बैठ गए और उनसे संवाद किया।

बीबीएयू में मुंशी प्रेमचंद जयंती पर संगोष्ठी, प्रेमचंद और तुलसीदास के साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता पर हुआ मंथन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में शुक्रवार को मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर 'समकालीन विमर्श: प्रेमचंद एवं तुलसीदास की प्रासंगिकता' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद और गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य को आज के समय में भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक बताते हुए कहा कि दोनों साहित्यकारों की रचनाएं भारतीय संस्कृति, सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की अमूल्य धरोहर हैं।कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. पवनपुत्र बादल उपस्थित रहे। इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोंडा के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. शैलेन्द्र नाथ मिश्र, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष प्रो. रामपाल गंगवार तथा कार्यक्रम संयोजक एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव मंच पर मौजूद रहे।कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन तथा बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और मुंशी प्रेमचंद के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय कुलगीत का गायन हुआ तथा अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव ने संगोष्ठी के उद्देश्य और रूपरेखा से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। मंच संचालन हिंदी अनुवाद अधिकारी संध्या दीक्षित ने किया।अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. सुनीता मिश्रा ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं 'गोदान', 'कफन', 'पूस की रात' और 'ईदगाह' आज भी भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने जिस संवेदनशीलता और गहराई से समाज के विभिन्न वर्गों के संघर्ष, पीड़ा और मानवीय संबंधों को साहित्य में स्थान दिया, वह आज भी प्रेरणास्रोत है। उन्होंने यह भी कहा कि गोस्वामी तुलसीदास की 'रामचरितमानस', 'विनय पत्रिका' और 'दोहावली' जैसी कृतियों ने भारतीय समाज को नैतिकता, भक्ति और लोककल्याण के आदर्शों से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है।मुख्य अतिथि डॉ. पवनपुत्र बादल ने कहा कि भारतीय साहित्य की मूल भावना लोकमंगल है और इसका सबसे प्रभावशाली स्वर तुलसीदास और प्रेमचंद की रचनाओं में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इन दोनों साहित्यकारों ने केवल साहित्य की रचना नहीं की, बल्कि समाज को दिशा देने, नैतिक मूल्यों को मजबूत करने और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कार्य किया।

संक्षेप

13 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले का वारंटी गिरफ्तार, इटौंजा पुलिस ने खेत से दबोचा

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ की इटौंजा थाना पुलिस ने अपराधियों और वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वर्ष 2013 के आर्म्स एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उसके खेत से हिरासत में लिया गया।पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त उत्तरी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इटौंजा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार 31 जुलाई 2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना इटौंजा क्षेत्र के महोना कस्बे में छापेमारी की गई। इस दौरान न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में आलम (40 वर्ष) निवासी मोहल्ला कटरा, कस्बा महोना, थाना इटौंजा को उसके खेत से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ वर्ष 2013 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमे में न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी था। पुलिस ने आरोपी को वारंट से अवगत कराते हुए हिरासत में लिया और उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध थाना इटौंजा में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोपी कृषि कार्य करता है।कमिश्नरेट पुलिस ने कहा कि न्यायालय से जारी वारंटों के तामील और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि कानून से बचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके।

पॉक्सो मामले का गैर जमानती वारंटी गिरफ्तार, अलीगंज पुलिस ने झोपड़पट्टी से दबोचा

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ की अलीगंज थाना पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म के मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे एक गैर जमानती वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई।पुलिस के अनुसार विशेष पॉक्सो न्यायालय, लखनऊ द्वारा वाद संख्या 166/2019 एवं मुकदमा संख्या 313/2017 में आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसी के अनुपालन में 31 जुलाई 2026 को अलीगंज थाना पुलिस ने आरोपी राम नरेश निवासी एलडीए अपार्टमेंट के पीछे स्थित झोपड़पट्टी, थाना अलीगंज को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा विचाराधीन है।

लखनऊ पुलिस की बड़ी पहल : 153 पीड़ित महिलाओं को दिलाया 18 .95 लाख रुपये का गुजारा भत्ता

लखनऊ। पारिवारिक न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों में पीड़ित महिलाओं को न्यायालय के आदेशों का वास्तविक लाभ दिलाने की दिशा में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने उल्लेखनीय पहल की है। महिला एवं अपराध शाखा की प्रभावी पैरवी, लगातार समन्वय और प्रतिवादियों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क के चलते 153 पीड़ित महिलाओं को कुल 18 लाख 95 हजार 100 रुपये का गुजारा भत्ता दिलाया गया है। इनमें वर्ष 2012 से लंबित मामले भी शामिल हैं।पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देशन, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार के मार्गदर्शन तथा पुलिस उपायुक्त महिला एवं अपराध ममता रानी की निगरानी में यह अभियान चलाया गया। वहीं, पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पंकज मिश्रा के निर्देशन में न्यायालय के आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया गया।महिला एवं अपराध शाखा ने संबंधित थानों, न्यायालय प्रशासन और प्रतिवादियों के बीच लगातार समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों में तेजी लाई। पुलिस कर्मियों ने प्रतिवादियों से व्यक्तिगत वार्ता कर उन्हें न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो–2026 : वैश्विक व्यापार और निवेश का बनेगा सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। आगामी 25 से 29 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस)-2026 के चौथे संस्करण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल व्यापारिक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रभावी मंच है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन का देश और विदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक निवेशक, खरीदार और उद्यमी इसमें भाग लें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ₹अनलिमिटेड पोटेंशियल₹ वाला प्रदेश बन चुका है और इंटरनेशनल ट्रेड शो इस क्षमता को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे उपयुक्त माध्यम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ₹मेक इन इंडिया₹ और ₹मेक फॉर द वर्ल्ड₹ के विजन को आगे बढ़ाने में इस आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।इस वर्ष ट्रेड शो की थीम ₹यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथः इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स₹ रखी गई है। आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.50 लाख से अधिक बी2बी खरीदारों, 4.50 लाख से अधिक आम आगंतुकों तथा 85 देशों से 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 4000 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू), 3200 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश समझौते तथा 13,500 करोड़ रुपये से अधिक की व्यावसायिक पूछताछ का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, जापान, रूस, ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया और ओमान सहित अन्य देशों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।बैठक में बताया गया कि इस बार ट्रेड शो में ओडीओपी, ओडीओसी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, स्टार्टअप, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा, स्वास्थ्य सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, खादी, वस्त्र, चमड़ा, फर्नीचर सहित 27 से अधिक प्रमुख क्षेत्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इससे प्रदेश की औद्योगिक, आर्थिक और निर्यात क्षमता का व्यापक प्रदर्शन एक ही मंच पर देखने को मिलेगा।मुख्यमंत्री ने नॉलेज सेशन को भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण बनाने के निर्देश दिए। इन सत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल व्यापार, बैंकिंग एवं वित्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नई श्रम संहिताएं, वैश्विक मुक्त व्यापार समझौते, ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण नीति, सड़क सुरक्षा तथा एमएसएमई जैसे समकालीन विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी इस आयोजन की पहचान बने। उन्होंने सभी दिनों में शास्त्रीय संगीत, कथक, लोकनृत्य, लोकगायन, भजन और ग़ज़ल जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आयोजन के निर्देश दिए, ताकि देश-विदेश से आने वाले मेहमान प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से भी परिचित हो सकें।बैठक में जानकारी दी गई कि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को जोड़ने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों और व्यापारिक मिशनों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। विभिन्न देशों के खरीदारों से संपर्क स्थापित कर बायर-सेलर मीट आयोजित की जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को नए वैश्विक बाजार उपलब्ध हो सकें।

छात्रों पर पैलेट गन...सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रदर्शन में शरारती तत्व आकर हिंसा करें तो कैसे रोका जाए?

दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा, जब बहुत गंभीर हालात में लाठीचार्ज और आंसू गैस से हिंसा काबू में न आने पर पुलिस को गोली चलाने की इजाजत होती है। अदालत ने ये भी कहा कि अगर कोई विरोध-प्रदर्शन शरारती तत्वों के कब्जे में आकर हिंसक हो जाए तो पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि पैलेट गन से कथित फायरिंग में घायल हुए प्रदर्शनकारियों का उचित इलाज किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि वो RAF के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखे, लेकिन साथ ही कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग करने वाले याचिकाकर्ता और पूर्व IPS अधिकारी यशोवर्धन आजाद से सवाल भी किए। जंतर-मंतर और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही।

याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इसमें काइनेटिक मैटेलिक प्रोजेक्टाइल (धातु का गोला) होता है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि लेकिन पुलिस के नियम खास हालात में इसके इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। जब तक कि आप खुद उन नियमों को चुनौती न दें। ग्रेडेड अप्रोच (चरणबद्ध तरीके) के तहत पैलेट गन का इस्तेमाल भी एक कदम है।

इसपर ग्रोवर ने कहा कि पैलेट रबर, प्लास्टिक और धातु के हो सकते हैं। ये धातु के थे और लोगों के शरीर से निकाले गए थे। जस्टिस बागची ने कहा कि हम किसी खास मामले में छर्रों (पेलेट्स) के इस्तेमाल की जांच करने के खिलाफ नहीं हैं। आपको हमें यह दिखाना होगा कि क्या छर्रों का इस्तेमाल 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स' (हालात के हिसाब से) के तौर पर किया जा सकता है। जबकि कुछ स्थितियों में गोलियां भी चलाई जाती हैं।

CJI ने कहा कि छर्रों के कथित तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को देखते हुए आपकी मांग यह होनी चाहिए कि कोर्ट इनके इस्तेमाल के लिए कोई प्रोटोकॉल तय करे। ग्रोवर ने कहा कि जी हां, सिर्फ़ धातु के छर्रों के लिए। जस्टिस बागची ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक नियम था कि गोला-बारूद बचाने के लिए गोलियां शरीर के किसी अन्य हिस्से के बजाय छाती पर चलाई जानी चाहिए। इसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह ज़रूर औपनिवेशिक दौर का नियम रहा होगा। जस्टिस बागची ने कहा कि उस नियम को रद्द कर दिया गया था। इसलिए आपको हमें ऐसे नियम दिखाने होंगे जहां छर्रों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से किया जा रहा हो।

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का आरोप है कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उन पर पैलेट गन चलाई गई। जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई, वे गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम करते हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर जनहित के मुद्दों को उठाना मेरा अधिकार है। मेरे लिए आज सबसे अहम मुद्दा छात्रों के साथ होने वाली बर्बरता है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाए। छात्रों के साथ जो हुआ, उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी लेने की शालीनता दिखाएं।

साथियों को भूखे मरता छोड़ खुद जीत का जश्न बनाती कॉकरोच जनता पार्टी

केवल आम जनता ही नहीं बल्कि खुद सीजेपी के आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे शर्मनाक बताया है। सीजेपी के मंच पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने वायरल वीडियो को लेकर कहा है कि जीत के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए।

राकेश सैन

गिद्धों का भी एक धर्म होता है, वो जिंदा जानवरों का मांस नहीं खातीं। वह प्रतीक्षा करती हैं उसके मरने की और प्राण छोडने के बाद ही लोथड़ों को नोचती हैं। लेकिन आज का इंसान गिद्ध से भी ज्यादा विभत्स हो गया लगता है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में प्राण गंवाने वाले 21 युवाओं के पोस्टर लगा कर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के नेता इन युवाओं का शोक मनाना तो दूर बल्कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद फाइव स्टार होटलों में कुल्हे मटकाते और बोतलों के ढक्कन खोलते दिखे। पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हो गया और लगभग एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतंत्र की नई-नई रखवाली कॉकरोच जनता पार्टी का धरना भी खत्म हो गया पर दो दिनों के भीतर ही इन नए नवेले लोकतंत्र के रखवालों का असली चेहरा सामने आने लगा है। नीट पेपर लीक होने के आक्रोश में मारे गए जिन युवाओं के पोस्टर लगा कर कोहराम मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने इतना तमाशा किया वो अपने साथियों को भूखे मरता छोड़ खुद फाइव स्टार होटलों में ठुमके लगाते और बीयर पार्टी करते हुए दिखाई दिए। लाशों के मंच पर लग रहे ठुमके और उड़ रही शराब की दुर्गंध इस बात की साक्षी है कि इस तरह की हरकत करने वालों के मनों में कितनी सड़ांध भरी होगी।

केवल आम जनता ही नहीं बल्कि खुद सीजेपी के आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे शर्मनाक बताया है। सीजेपी के मंच पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने वायरल वीडियो को लेकर कहा है कि जीत के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। सोनम ने कहा कि सफलता पाने के साथ-साथ सम्मान और विनम्रता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। सीजेपी समर्थकों ने भी पार्टी के वीडियो की आलोचना की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य और कमेंटेटर-यूट्यूबर मेघनाद ने सीजेपी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद दर्जनों प्रदर्शनकारी सडक़ों पर बेघर और भूखे रह गए थे तब ये नेता पार्टी कर रहे थे। इंस्टाग्राम पोस्ट में मेघनाद ने कहा कि उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने उन

दर्जनों प्रदर्शनकारियों के लिए यात्रा और भोजन का इंतजाम किया जो सीजेपी नेताओं के साथ एक महीने से ज्यादा समय से जंतर-मंतर पर डेरा डाले हुए थे। मेघनाद ने सीजेपी पार्टी के वीडियो के बारे में लिखा, 'मैं यह सुबह 4 बजे देख रहा हूं। मैंने और कुछ लोगों ने पिछले दो दिनों में अपने पैसे से सीजेपी के उन वॉलंटियर्स और प्रदर्शनकारियों को घर भेजा है जिन्हें बेसहारा और भूखा छोड़ दिया गया था। मैं कुछ नहीं कहने वाला था लेकिन मैंने यह वीडियो देखा और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।' उन्होंने सीजेपी के लिए कड़े शब्दों के साथ अपनी पोस्ट खत्म की, 'जब आप पार्टी कर रहे थे तब दिल्ली में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और छात्र भूखे रह गए क्योंकि आपने परवाह न करने का फैसला किया था। बधाई हो सीजेपी आखिरकार आप भी एक और राजनीतिक पार्टी बन ही गए।'

ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन के खत्म होने के दो दिनों बाद ही उसमें फूट पड़ती दिख रही हो। आखिर पड़े भी क्यों ना, कुछ लोगों ने देश के युवाओं के आक्रोश का लाभ उठाया और देखते ही देखते वे दुनिया में अभियानवादियों के स्टार बन गए। उनकी कही बातें अब इंटरनेशनल मीडिया में गूंज रही हैं और उनकी भाव भंगिमा ऐसी है मानो उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो। लेकिन क्या फाइव स्टार होटलों में गुलछर्रे उड़ाने वाले जेन-जी नेता बताएंगे कि आंदोलन के दौरान कितनी बार पेपर लीक के मृतकों को याद किया गया। केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद काक्रोचों ने अहंकारमयी मुद्रा में आकर कहा कि 'झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए।' सीजेपी के नेता जीत के जश्न में उन लोगों को क्यों भूल गए जिन्होंने अपनी जानें दीं। उन परिवारों को क्यों नहीं बुलाया गया जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। असल में कुछ अभियानवादियों ने इन 21 युवाओं की लाशों का मंच की तरह उपयोग किया और अपना कद बड़ा कर चलते बने। कहने को ये जेन-जी वाले शिक्षा नीति में सुधार का नारा लेकर आए थे परंतु इनका असली नारा यही दिखता है कि 'अपना काम है बनता-भाड़ में जाए जनता।' ऐसे मुर्दाखोर आंदोलनकारियों पर तो शायद गिद्धों को भी शर्म आ जाए।

व्यंग्य

पूरी लीला ही पैसे से आयोजित-प्रायोजित

हां, हिंदू राष्ट्र को सोनम वांगचुक या जीडी अग्रवाल जैसे 'कॉकरोचों' से नहीं, बल्कि अडानी, अंबानी, चढ़ावा चोरों और ट्रंप जैसे लोगों से मतलब है। इन्हीं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता है, क्योंकि पूरी लीला ही पैसे से आयोजित-प्रायोजित है। आखिर कलियुग में भगवान तप से नहीं, मार्केटिंग से पैदा होते हैं और आस्था के नाम पर भीड़ को ठगना परमोधर्म है।

पिछले बारह वर्षों में क्या हुआ है? चाहे 'श्वेत (काली की जगह) अर्थव्यवस्था' का समय हो, 'गंगा शववाहिनी' का दौर, 'अमृतकाल' का आख्यान या 'विकसित भारत' के नारे-हर चरण में सबसे बड़ा निवेश मार्केटिंग पर हुआ। मार्केटिंग ने ही वह वातावरण, वह लेन-देन बनाया, जिसमें अडानी-अंबानी नए जगतसेठ बनकर उभरे। दूसरी और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर शी जिनफिंग, पुतिन सभी के लिए भारत विशाल बाजार बना। पैसे की भूख, पैसे के जलवे, पैसे की माया का सीधा असर भक्तों पर भी पड़ा। इनके मन में यह विश्वास बैठाया गया कि भारत अभूतपूर्व गति से दौड़ रहा है, दुनिया भारत की ताकत स्वीकार कर रही है, मुक्त व्यापार समझौते हो रहे हैं और विश्व भारत के सामने नतमस्तक है।

सच्चाई है कि जब अडानी दुनिया के बड़े खरबपतियों में शामिल हुए तो भक्तों ने इसे भी हिंदुओं की आन-बान-शान माना। बाद में जब इस चमक की परतें उखड़ीं, तब भी शेयर बाजार के खेल ने करोड़ों मध्यवर्गीय युवाओं को अपनी किस्मत आजमाने के सपने में बांधे रखा। इससे किसका कितना नुकसान हुआ, यह अलग प्रश्न है। लेकिन लाभार्थियों के खातों में सरकारी धन पहुंचाने से लेकर शेयर बाजार में करोड़ों युवाओं की सट्टेबाजी तक, एक ऐसा सम्मोहन रचा गया जिसमें भक्ति पुख्ता होती गई। मंदिरों में चढ़ावा बढ़ता है वही उसी चढ़ावे से हिंदू राष्ट्र की दुकानों में भी चौतरफा रौनक है।

सचमुच कलियुगी हिंदू राष्ट्र की स्थिरता की कई वजहों में एक कारण मंदिर, चढ़ावा, कृपा, पैसा, क्रोनीवाद और मार्केटिंग का वह मायाजाल है, जिसकी गहराई तभी समझ में आएगी जब लुटियंस दिल्ली के नए 'सेवा तीर्थ' की परतों को कोई उधेड़े। लुटियन का नया इकोसिस्टम केवल जवाबदेही-विहीन नहीं है, बल्कि संस्थागत लूट की वह ऐतिहासिक व्यवस्था है कि यदि दिल्ली को लूटने वाले नादिरशाह या मुगल बादशाह भी उसे देखें तो शर्मिंदा हो जाएं। उन्होंने दिल्ली को लूट का मात्र चरागाह माना था, जबकि अब वह लूट का तीर्थ है। लेकिन मजाल जो कोई गंभीर सवाल उठे या दास्तान बाहर आए।

उस नाते राम मंदिर से जुड़े विवाद या चंपत राय एंड पार्टी के प्रसंग बहुत छोटे हैं। वे तो केवल राजनीतिक हिसाब-किताब का हिस्सा हैं। असली खेल खरबपति क्रोनी पूंजीपतियों का है और ट्रंप, शी जिनफिंग, पुतिन जैसे उन वैश्विक नेताओं का है, जिन्होंने आर्थिक-सामरिक रिश्तों में भारत को सौ टका पराश्रित देश बना डाला है।

ब्लॉग

बढ़ते अरबपति गतिशील इकोनोमी के परिचायक

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि देश की इकोनोमी में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा पिछले दिनों में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों का ही विश्लेषण करें तो दो बातें साफ हो जाती है कि देश में अरबपतियों की संख्या में बेतहासा बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी और इंकमटैक्स रिटर्न भरने वालों की भी संख्या में इजाफा हो रहा है। संसद में पेश आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ हो रहा है कि आयकर रिटर्न में 100 करोड़ से अधिक की आय बताने वालों की संख्या 2021-22 की 142 से बढ़कर 576 हो गई है। आयकर रिटर्न के अनुसार पिछले सालों एक अरब से अधिक आय वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

इसे गतिशील अर्थ व्यवस्था का परिचायक माना जा सकता है। पिछले पांच साल के आंकड़ों का ही विश्लेषण किया जाएं तो देश में बेरोजगारी की दर में भी कमी आई है। हांलाकि सरकार इसके लिए अपनी लोककल्याणकारी नीतियों को श्रेय देती है। आयकर प्रक्रिया में सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सीधा लाभ, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन , पानी बिजली आदि आदि की जनहितकारी योजनाओं और निवेशोन्मुखी माहौल से देष में तेजी से सुधार का माहौल बना है। हांलाकि देश के कुल परिसंपत्तियों में 50 फीसदी से अधिक लोग केवल 2 प्रतिशत की ही हिस्सेदारी रखते हैं। अच्छी बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रही है और युवकों के साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक पक्ष यह है कि समन्वित प्रयासों से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए क्षेत्रों को तेजी से व योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया गया है। परंपरागत क्षेत्रों के साथ ही नए क्षेत्रों में अवसर खुले हैं और इसका सबसे अधिक लाभ युवा पीढ़ी उठा रही है। एक आंकड़ें के अनुसार 425 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले 3040 में से 1696 ऐसे उद्यमी है जो नई पीढ़ी और पहली पीढ़ी के हैं। नई पीढ़ी से मतलब यह है कि यह वे नए लोग है जो पंरपरागत या धनकुबेरों के परिवारों से नहीं आते अपितु अपने स्तर पर इस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। यही अर्थव्यवस्था का सकारात्मक पक्ष हो जाता है। सरकारी नीतियों और युवाओं में नया करने की ईच्छा शक्ति का परिणाम है कि नए क्षेत्रों में स्टार्टअप या एमएसएमई के मध्यम से युवाओं ने पहल की और अर्थ व्यवस्था को गति देने के साथ ही निवेश, रोजगार के अवसर विकसित किये। सरकार ने भी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानि की पीएलआई से युवाओं को जोड़कर कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त हुए हैं। साल दर साल आयकर रिटर्न भरने वाले और आयकर देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी इसका उदाहरण है। यह सब सरकार की सकारात्मक नीतियों से ही संभव हो सकता है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सरकार की नीतियों का अर्थ व्यवस्था को गति देने में खास भूमिका होती है। आज दुनिया के देशों में ईज ऑफ डूइंग पर जोर दिया जा रहा है। देशों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और देशी विदेशी निवेश बहुत कुछ सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। बुनियादी ढांचा विकास, उद्योगों को प्रोत्साहन, सेवा क्षेत्र में विस्तार, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, जीएसटी एक देश एक कर की नीति, डिजिटल भुगतान और विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार से औद्योगिक माहौल बनता है। एक बात और की एमएसएमई आर्थिक विकास की रीढ होती है। इसे ग्रोथ इंजन भी कहा जा सकता है क्योंकि इससे अर्थ व्यवस्था को गति मिलती है तो स्थानीय स्तर पर बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर भी एमएसएमई सेक्टर में ही विकसित होते हैं। यही कारण है प्रोडक्सन लिंक इंसेटिंव जैसी योजनाओं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से युवा रोजगार मांगने की जगह रोजगार प्रदाता बनने का सपना देखता है और इसमें कोई दे राय नहीं कि एमएसएमई सेक्टर में अधिक रोजगार के अवसर विकसित होते हैं। अर्थ व्यवस्था को गति मिलती है। हांलाकि बड़े उद्योगों का अपना महत्व हे और उससे इंकार नहीं किया जा सकता। एक और बात यह है कि देश में निवेशोन्मुखी माहौल बन रहा है। राज्यों द्वारा अब निवेशकों को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिए अन्य राज्यों के साथ ही प्रोस्पेक्टिव विदेशों में रोड शो सहित विभिन्न आयोजन कर निवेश का माहौल बनाया जाता है। राज्यों द्वारा निवेश सम्मेलन और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आयोजन आम होते जा रहे हैं। इसके परिणाम भी आने लगे हैं। यह भी साफ है कि उद्योग लगाने के लिए निवेश आयेगा तो रोजगार, कारोबार के साथ ही नई तकनीक और इसके साथ ही अन्य कई चीजें आयेगी और उसका लाभ देश और देश की अर्थ व्यवस्था को ही मिलेगा।

सवाल एक और उभरता है कि अमीर-गरीब की खाईं अधिक गहरी नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक पक्ष यह है कि रोजगार और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। नागरिकों की आय बढने लगी है और इसका समाज के समग्र विकास पर असर पड़ता है। आय बढ़ेगी या रोजगार उपलब्ध होगा तो रहन-सहन, जीवन यापन के स्तर में सुधार होगा। लोगों की आय बढ़ेगी और आय से बाजार में मांग आपूर्ति में बदलाव आयेगा और इससे इकोनोमी को गति मिलेगी। अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी अच्छी बात है पर अमीर गरीब के बीच खाईं पाटने के प्रयास अभी नाखाफी ही लग रहे हैं।

न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन...जज ने कोडीन कफ सिरप केस की सुनवाई से खुद को किया अलग

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोडीन कफ सिरप केस से जुड़ी 74 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सिंगल बेंच के जस्टिस कृष्ण पहल ने खुद को इससे अलग कर लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण ने बेहद कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश तक पहुंच बनाने का कोई भी प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बड़ा हमला है। उन्होंने इसे न्यायालय के इतिहास का काला दिन करार दिया। जस्टिस कृष्ण पहल ने सभी मामलों को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के सामने नई पीठ के गठन के लिए भेजने का आदेश दिया। यह आदेश उन्होंने भोला प्रसाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया।

जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल ने कोडीन कफ सिरप केस में जमानत अर्जी पर आदेश जारी करने से पहले खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। कोर्ट ने अन्य पीठ नामित करने के लिए लगभग 80 अर्जियां चीफ जस्टिस को भेज दीं। जानकारी के मुताबिक कोडीन कफ सिरप तस्करी के आरोपी पक्षकार ने जज से संपर्क करने की कोशिश की थी। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि 'इतिहास का यह काला दिन है। कोर्ट ने कहा कि न्याय होना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए।

जज से संपर्क साधने की कोशिश

बता दें कि जस्टिस कृष्ण पहल की कोर्ट में भोला प्रसाद की जमानत अर्जी की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई पूरी कर ली थी और आदेश बाद में सुनाया जाना था। सुनवाई के बाद पक्षकारों की ओर से कथित तौर पर पीठासीन जज तक सीधे पहुंच बनाने और संपर्क साधने की कोशिश की गई।

न्यायपालिका में जनता का भरोसा होगा कमजोर

कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो न्यायपालिका में जनता का भरोसा कमजोर होगा। अपने आदेश में जस्टिस पहल ने कहा कि यह घटना कोर्ट के इतिहास में एक 'काला दिन' है। उन्होंने कहा कि न्याय होना ही काफी नहीं, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है।

अब 7 अगस्त को होगी सुनवाई

उन्होंने कहा कि अगर फैसला उसी पक्ष के हक में आता, जिसका पक्ष सुनवाई में मजबूत लग रहा था। तो इससे यह गलत धारणा बन सकती थी कि फैसला बाहरी दबाव में दिया गया। इन हालात को देखते हुए कोर्ट ने खुद को मामले से अलग करने का फैसला लिया और सभी संबंधित लगभग 80 जमानत मामलों को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। ताकि उन्हें किसी उपयुक्त पीठ को सौंपा जा सके। सभी मामलों को अब 7 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी।

एक मंच पर गूंजीं शहनाइयां और निकाह की सदाएं, 207 जोड़ों ने थामा जीवनभर का साथ

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय सुल्तानपुर। विकास खंड बल्दीराय परिसर शुक्रवार को खुशियों,उत्साह और सामाजिक सौहार्द का केंद्र बना रहा।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित भव्य समारोह में 207 जोड़ों ने एक साथ नए जीवन की शुरुआत की।इनमें 205 हिंदू जोड़ों का वैदिक रीति-रिवाज से विवाह कराया गया,जबकि दो मुस्लिम जोड़ों का निकाह इस्लामी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ।एक ही मंच पर दोनों धर्मों की परंपराओं के साथ संपन्न हुए इस आयोजन ने सामाजिक समरसता और गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल पेश की।शहनाइयों की मधुर धुन,वैदिक मंत्रोच्चार और निकाह की रस्मों के बीच नवदंपतियों ने जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया।पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा और परिजनों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती रही।समारोह की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है।इससे जरूरतमंद परिवारों को सम्मानपूर्वक बेटियों का विवाह कराने में बड़ी सहायता मिल रही है।विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद,समृद्ध और मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना की।इस अवसर पर जिला परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह, एसडीएम बल्दीराय प्रभात सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण, एडीओ अरविंद कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कागजों में मृत महिला पहुंची हाईकोर्ट, बोली...मैं जिंदा हूं साहब, मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। सरकारी कागजों में मृत घोषित हो चुकी चंदा देवी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच कर बोली... मैं जिंदा हूं साहब, मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए। महिला की गुहार पर हैरान न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने शुक्रवार को प्रयागराज के डीएम, जिला पूर्ति अधिकारी और प्रतापपुर, हंडिया के वारी के ग्राम प्रधान को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। कोर्ट ने सुनवाई के वक्त महिला को भी मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

कोर्ट पहुंची महिला ने बताया कि वह प्रतापपुर, हंडिया के वारी गांव की रहने वाली है। पति साधुराम का निधन हो गया है लेकिन मैं जिंदा हूं। इसके बावजूद सरकारी दस्तावेजों में उसे भी मृत घोषित दर्ज कर दिया गया है। इसके कारण न तो राशन कार्ड बन पा रहा है और न ही उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। महिला ने दावा किया कि कई बार

अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई।

मजबूर होकर उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने इसे नागरिक के मूल अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला माना। कहा कि यदि कोई जीवित व्यक्ति सरकारी अभिलेखों में मृत दर्ज है तो यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि उसके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

कोर्ट ने जिले के आला अधिकारियों को अदालत में पेश होकर यह स्पष्ट करने को कहा कि आखिर जीवित महिला को किन परिस्थितियों में नागरिक आपूर्ति विभाग ने उन्हें मृत दर्ज कर दिया। अगर भूल है तो अब तक इसे सुधारा क्यों नहीं गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डीएम और डीएसओ यह भी सत्यापित करना होगा कि चंदा देवी वास्तव में साधुराम की विधवा हैं या नहीं।

मानकों के अनुरूप मिले बंदियों को सुविधायें

जौनपुर। जनपद की कारागार व्यवस्था का निरीक्षण के उद्देश्य से शुक्रवार को जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने जिला कारागार का मासिक औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, बैरकों, भोजनालय, चिकित्सालय, साफ-सफाई तथा पेयजल व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कारागार प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी बंदियों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सुरक्षा कर्मियों को नियमित जांच, सतर्क निगरानी और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

'सारे कष्ट होंगे दूर' : सपना आने के बाद बना दी मजार, हंगामे के बाद खुद हटाया निर्माण, युवक ने मानी गलती

आर्यावर्त संवाददाता

सिंधौली (शाहजहांपुर)। भाई की मौत और बाबा की आंखों की रोशनी जाने से परेशान ढकिया हमीनगर गांव के धीरज ने बाजपुर गांव स्थित अपनी जमीन पर पंचपीर की मजार बना दी। धीरज के मुताबिक, उसे सपना आया था कि ऐसा करने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मजार बनाने पर हिंदू संगठन समेत गांव के लोगों ने आपत्ति जताई। हंगामा होने और पुलिस के कार्रवाई की चेतावनी देने पर उसने खुद निर्माण हटा दिया।

सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि ढकिया हमीदनगर के रहने वाले धीरज की व्यक्तिगत जमीन रोड के किनारे है। यहां पहले से एक देवस्थान बना हुआ है। उसी के पास धीरज ने तीन-चार माह पूर्व एक चबूतरा बनवाया था। उसके छोटे भाई की असमय मौत हो गई थी और तीन-चार महीने पहले बाबा की आंखों की रोशनी चली गई थी। धीरज का

कहना है कि चार-पांच दिन पहले उसे सपना आया कि उसके घर से बीमारियां और अन्य कष्ट से बचने एक ही रास्ता है कि चबूतरे पर पंचपीर बाबा की मजार बना दो।

धीरज ने बुधवार रात को बिना किसी अनुमति के चबूतरे पर मजार बना दी। बृहस्पतिवार सुबह लोगों ने मजार को बना देखकर विरोध किया। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी, जिला महासचिव शुभम मिश्रा पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए। मजार का निर्माण देख जिलाध्यक्ष ने हिंदू युवा वाहिनी के बरेली मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित दीक्षित को जानकारी दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर आ गई।

पुलिस ने समझाया कि बगैर अनुमति के निर्माण कराना अवैध है। इस पर धीरज ने खुद ही बनाया गया ढांचा हटा दिया। वहीं, हिंदू संगठन ने चबूतरे पर भगवा झंडा लगा दिया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि ग्रामीण को समझाया गया है। उसने अपनी कानून की जानकारी न होने की बात कहते हुए अपनी गलती मान ली और निर्माण खुद हटा दिया। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

अली असगर की शहादत को किया याद

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। नगर के बलुआ घाट मोहल्ला स्थित मकबूल मंजिल में गुरुवार की रात अंजुमन हुसैनियां की शब्बेदारी का दौर शुरू हुआ जो शुक्रवार की सुबह खत्म हुआ। इसमें मशहूर 5 अंजुमनों के अलावा शहर की प्रमुख अंजुमनों ने पूरी रात कर्बला के सबसे कमसिन शहीद जनाबे अली असगर की याद में अपने दर्द भरे नौहे पेश किया। अलविदाई मजलिस के बाद गहवारे अली असगर और अलम, ताबूत निकाला गया जिसकी जियारत के लिए हजारों लोग मौजूद रहे।शब्बेदारी का आगाज तिलावते कलाम-ए-पाक से सै. अली हसनैन श्यान ने किया। मजलिस को खेताब करते हुए मौलाना सैय्यद सज्जाद हुसैन बिहार ने कहा कि इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे जनाब अली असगर जिनकी उम्र छह माह की थी। यजीदी फौजों ने उस वक्त कर्बला के मैदान में तीन भाल के भारी भरकम तीर से इमाम के हाथों में शहीद कर दिया। जब वे यजीदी फौजों से इस बच्चे के लिए दो कतरा पानी पिलाने के लिए मांग रहे थे। अली असगर 3 रोज के भूखे-प्यासा थे पर जालिमो को उनपर भी रहम नही आया। इसके बाद नौहा मातम का सिलसिला मिसरा तरहे ष..जबीने दीने हक पे असगरे बेशीर लिख देना..... व तबस्सुमें अली असगर का तर्जुमा ही नहीष पर नौहा मातम शुरू हुआ। इस अवसर पर अंजुमने परवाने अजा शिकारपुर बुलंदशहर, अंजुमन मखदुमियाँ गाजीपुर,अंजुमन हैदरी सेथल बरेली, अंजुमन जाफरिया जफराबाद जलालपुर अम्बेडकरनगर, अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुलतानपुर के अलावा शहर की प्रमुख अंजुमनों ने अपने दर्द भरे नौहे पढ़कर कर्बला के सबसे कमसिन शहीद अली असगर को अपना नजराने अकीदत पेश किया।

ग्राम प्रधान पर मजदूर की हत्या का आरोप

जौनपुर। षाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम-मजडीहा के एक गरीब मजदूर पत्नी ने अपने पति की हत्या किये जाने का आरोप ग्राम प्रधान पर लगाया है। उसका कहना है कि प्रधान ने मेरे पति को बुरी तरह से पीटा और गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां तीन दिन बाद उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने प्रधान के खिलाफ कार्यवाही नहीं किया और पोस्ट मार्टम के बाद लाष दफनवा दिया। मांग किया कि लाष का निकलवा कर फिर से डाक्टरों की संयुक्त टीम से जांच करायी जाय। उक्त गांव की गुलावती पत्नी चन्दन राजभर का पति मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण-पोषण करता है। वह ग्राम प्रधान मो० साजिद उर्फ चुन्नू के यहाँ मुर्गी फारम की देख-रेख करती थी। बीते 16 जुलाई को रात्रि को ग्रामप्रधान द्वारा तीन दिन तक अपने यहां रोक लिया गया जिसकी जानकारी हम प्रार्थिनी के पति को होने पर ग्राम प्रधान के घर

अनोखी कांवड़, भोले हैं विराजमान, 10 क्विंटल की कार दांतों से खींच हरिद्वार से अलीगढ़ ला रहे नरेंद्र

आर्यावर्त संवाददाता

अलीगढ़। भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था अनोखा उदाहरण पेश करते हुए जट्टारी के गांव छजूपुर निवासी 25 वर्षीय नरेंद्र चौधरी उर्फ टिकना कार को दांतों से खींचते हुए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। कार पर 11 लीटर गंगाजल और भगवान शिव की प्रतिमा रखी है। कार व प्रतिमा सहित कुल वजन करीब 10 क्विंटल बताया जा रहा है।

नरेंद्र ने बताया कि उन्होंने 10 जुलाई को हरिद्वार से यात्रा शुरू की थी और 10 अगस्त तक गांव पहुंचने का लक्ष्य है। इसके बाद सावन के दूसरे सोमवार को गांव के प्राचीन अंडारेश्वर महादेव मंदिर में 11 लीटर गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। बृहस्पतिवार शाम तक वह जेवर हवाई अड्डा पार कर चुके थे। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और भारत को हिंदू राष्ट्र

घोषित करने की मांग को जन-जन तक पहुंचाना है। उनकी यात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं।

गांव के कई युवक भी साथ ला रहे हैं कांवड़

नरेंद्र के साथ गांव के हरिओम शर्मा, मोना बाबा, शंकर दादा, जगत जाट और कालू भी अपने कंधों पर 41 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। नरेंद्र ने बताया कि करीब आठ महीने पहले उन्होंने 50 किलो चीनी की बोरी उठाकर दांतों से वजन खींचने की शुरुआत की थी। इसके बाद ट्रैक्टर, ट्रक और एक साथ छह वाहनों तक को दांतों से खींचने का दावा किया। मई में वह अपने गांव से वृंदावन तक कार खींचकर संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए भी पहुंचे थे। पिता के निधन के बाद वह पैतृक खेती संभाल रहे हैं।

संक्षेप

सिपाही का जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास

जौनपुर । बरसठी थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने शुक्रवार सुबह कथित तौर पर विषाक्त पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना से थाने में हड़कंप मच गया। साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया गया। शुरुआती जानकारी में पारिवारिक कलह को घटना की वजह बताया जा रहा है। मिर्जापुर निवासी कांस्टेबल विवेक गौड़ पिछले दो वर्षों से बरसठी थाने में तैनात हैं और मुंशी का कार्य देख रहे थे। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे उन्होंने अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बातचीत की। इसके कुछ देर बाद उन्होंने विषाक्त पदार्थ पीने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद एक अन्य सिपाही ने विवेक को रोकने की कोशिश की और उनके हाथ से कटोरा गिरा दिया। हालांकि, विवेक ने बचा हुआ कुछ विषाक्त पदार्थ उठाकर पी लिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

ट्रैक्टर से दबकर महिला की मौत

जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के शुक्रवार की दोपहर शंकरमंडी चुंगी से दहीदपुर नाला मार्ग के बीच हैदरपुर के पास बिना रजिस्ट्रेशन तेज रफ्तार मिट्टी लदा ट्रैक्टर पीछे से बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई पुत्र बाल बाल बच गए सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर का घेराव कर लिए चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मिट्टी लदा ट्रैक्टर थाने ले गई। जमालपुर गांव निवासी यादवेंद्र मौर्या की पत्नी राजदेई 65 वर्ष अपने बेटे ज्ञान सिंह के साथ घर से जौनपुर दवा लेने जा रही थी कि शकरमंडी चुंगी दहीदपुर नाला मार्ग हैदरपुर के पास बिना रजिस्ट्रेशन अवैध खनन मिट्टी लदा ट्रैक्टर पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दिया जिसमें मां राजदेई ट्रैक्टर की टायर से दबकर मौके पर मौत हो गई।

अधेड़ की ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत

जौनपुर। गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के आरे गांव निवासी 50 वर्षीय उपेंद्र पाठक पुत्र शिवनाथ पाठक की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उपेंद्र पाठक गुरुवार शाम करीब 6 बजे अपनी पत्नी सुप्रिया और छोटे बेटे के साथ बाइक से आजमगढ़ जनपद के एकौना थाना क्षेत्र के सनुवाडीह स्थित अपनी ससुराल गए थे। देर रात करीब 10 बजे उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए आरोप लगाया है कि उपेंद्र पाठक की हत्या करने के बाद शव को चादर के सहारे पंखे से लटका दिया गया, ताकि घटना आत्महत्या प्रतीत हो। घटना की सूचना मिलते ही आजमगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मनाया समरसता संपर्क सम्मान समारोह

जौनपुर। भाजपा नगर उत्तरी मंडल द्वारा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर चलाए जा रहे रुसमरसता अभियान के अंतर्गत मंडल अध्यक्ष श्रीमती सारिका सचिन सोनी के नेतृत्व में जोगेश्वर नाथ महादेव मंदिर आलमगंज एवं माता विंध्यवासिनी मंदिर ताड़तला के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन एवं सम्मानित कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजपा उत्तर प्रदेश राजेश श्रीवास्तव बच्चा भईया एडवोकेट ने कहा है भाजपा ही सर्व समाज समुदाय धर्मगुरुओं का सम्मान करती है।ब्लॉक प्रमुख करंजकला प्रतिनिधि सुनील यादव ममन ने कहा है पूज्य संत रविदास गुरुजी के पदचिह्नों पर चलते हुए मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी जौनपुर के हर वर्ग के नागरिकों का सम्मान करते है और करते रहेंगे। कृष्णकांत साहू नगर उपाध्यक्ष राघवेंद्र दुबे, नगर उपाध्यक्ष शुभम कन्नौजिया, नगर मंत्री विकास अग्रहरि , सनी चैधरी , सोशल मीडिया प्रभारी सत्यम सोनी , नगर कार्यसमिति सदस्य गिरिजेश कुमार श्रीवास्तव आदि पूजन किया।

खोदाई हुई तो मिल सकता है 2,000 साल पुराना नगर, प्राचीन नगरीय संरचना के अवशेष मिले

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। रायबरेली जिले के हरचंदपुर क्षेत्र में स्थित ओई भीट गांव में कथित सुरंग मिलने की चर्चा के बीच पुरातत्व विभाग की प्रारंभिक जांच ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। विभाग की टीम का कहना है कि यहां सुरंग होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, बल्कि जो प्राचीन अवशेष सामने आए हैं, वे करीब 2000 वर्ष पुराने कुषाणकाल की एक नगरीय संरचना की ओर संकेत करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और राज्य सरकार वैज्ञानिक तरीके से विस्तृत सर्वेक्षण और खोदाई कराएं, तो यहां एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर के प्रमाण मिल सकते हैं। करीब एक सप्ताह पहले हुई तेज बारिश के बाद गांव के किसान सुशील मौर्या के खेत में गड्ढा हो गया था। सुशील जब मौके पर

पहुंचे तो उन्हें गड्ढे में पक्की ईंटों से बनी दीवार दिखाई दी। इसकी सूचना लगते ही स्थानीय लोगों ने इसे सुरंग मान लिया। बुधवार को लखनऊ से पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया।

सहायक पुरातत्व अधिकारी डॉ. मनोज कुमार यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यहां से मिट्टी के बर्तन तथा अन्य प्राचीन अवशेष मिले हैं, जो लगभग दो हजार वर्ष पुराने यानी कुषाणकाल के प्रतीत होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अवशेष किसी सुरंग के नहीं हैं। मोटी ईंटों की दीवारें और अन्य संरचनात्मक साक्ष्य एक विकसित प्राचीन नगरीय बसावट की ओर संकेत करते हैं। इसकी जांच कराई जाएगी।

ऐतिहासिक स्थलों में शामिल हो सकता है ओई भीट

पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगे की जांच में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि होती है, तो ओई गांव उत्तर भारत के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में शामिल हो सकता है। इसकी तुलना बिहार के पटना, मधुबनी और सिवान तथा यूपी के मथुरा, दिल्ली और हरियाणा व पंजाब के प्राचीन नगरों से जुड़े पुरातात्विक स्थलों से की जा सकेगी।

ग्रामीणों ने की गांव में खोदाई कराने की मांग

खेत मालिक सुशील मौर्या ने बताया कि सन 1995-96 और 1996-97 में भी यहां प्राचीन अवशेष मिलने के बाद पुरातत्व विभाग की टीम ने सर्वे किया था लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते सर्वे का काम आगे नहीं बढ़ सका था। जिसका ब्योरा खसरा नंबर 141 में दर्ज है। वहीं पूर्व प्रधान एवं प्रधान प्रधान प्रतिनिधित्व हरिश्चंद्र मौर्य, राममिलन, मनोज कुमार सहित कई ग्रामीणों ने सरकार से ओई भीट की खोदाई कराने की मांग की है।

कांग्रेस का दावा , लगायेंगे दस हजार पौधे

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। हर व्यक्ति को प्रकृति और पेड़ पौधों को बचाने और उसे संरक्षित करने के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए, वृक्षारोपण धरती का सबसे पुनीत और महत्वपूर्ण कार्य है। उक्त बातें कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष डा प्रमोद कुमार सिंह ने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान के नेतृत्व में शुक्रवार को नगर के बड़ी मस्जिद के पास कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित पौध वितरण कार्यक्रम में कहा। कहा कि प्राकृतिक संतुलन खो बनाये रखने के लिए वृक्षों का व्यापक और पर्याप्त मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमें प्राणवायु देने के साथ ही मानसून और भीषण गर्मियों से राहत देता है, इसलिए हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है कि वृक्षारोपण कर उन्हें संरक्षित करें साथ ही अंधाधुंध होने वाली पेड़ों की कटाई को रोकने में सबको परस्पर सहयोग करना चाहिए, वृक्ष मानव जीवन का प्राण है। डा. प्रमोद कुमार सिंह ने संकल्प लेते हुए कहा कि जौनपुर कांग्रेस पूरे जनपद में अपने पास से दस लाख पौधे लगवायेगी। दस हजार पौधों को वितरित किया तथा हर व्यक्ति को पौधों के संरक्षण की शपथ दिलाई। बंशीधर शर्मा, राजकुमार गुप्ता, इरशाद खान राजू , राजकुमार गुप्ता, इस्तेखारूल प्रधान,जैद सिद्दीकी,अजीम जौनपुरी,साद सिद्दीकी, मसूद अहमद,परवेज आदि मौजूद रहे।

क्या बिगड़ी हुई ओरल हेल्थ भी बढ़ाती है शुगर लेवल?

बहुत से लोगों को लगता है कि डायबिटीज का असर सिर्फ ब्लड शुगर पर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज का असर आपके दांतों और मसूड़ों पर भी पड़ सकता है। और खास बात ये है कि इन दोनों का कनेक्शन दोनों तरफ से होता है। यानी डायबिटीज होने पर दांतों और मसूड़ों की दिक्कतों का खतरा बढ़ सकता है। अगर ओरल हेल्थ ठीक नहीं है, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना भी मुश्किल हो सकता है।

जब ब्लड शुगर लंबे समय तक ज्यादा रहता है, तो लार में भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मुंह में मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसकी वजह से दांतों पर प्लाक जम सकता है, दांतों में कीड़ा लग सकता है और मसूड़ों की बीमारी भी हो सकती है।

लार का कम बनना

डॉक्टर शिखा शर्मा, डेंटल सर्जन कहती हैं कि डायबिटीज की वजह से कुछ लोगों के मुंह में लार भी कम बनने लगती है, जिससे मुंह सूखा सूखा रहने लगता है। लार हमारे मुंह से खाने के छोटे छोटे टुकड़े और बैक्टीरिया साफ करने में मदद करती है। इसलिए जब लार कम बनती है, तो दांतों में कैविटी और मुंह में इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है।

इसके अलावा, डायबिटीज में शरीर को ठीक होने में भी थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए मसूड़ों की छोटी सी परेशानी या दांतों का कोई इलाज होने के बाद भी रिकवरी में ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन इसका असर सिर्फ एक तरफ नहीं होता। अगर मसूड़ों की बीमारी ज्यादा बढ़ जाए, तो शरीर में लगातार सूजन बनी रह सकती है।

इंसुलिन का ठीक से काम न कर पाना

इससे इंसुलिन का सही तरीके से काम करना मुश्किल हो सकता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करना भी कठिन हो सकता है। यानी कई बार एक ऐसा चक्र बन जाता है, जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मसूड़ों की बीमारी को बढ़ाती है और मसूड़ों की बीमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना और मुश्किल कर देती है।

इसलिए दांतों और मसूड़ों का ख्याल रखना सिर्फ अच्छी स्माइल के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि डायबिटीज को मैनेज करने का भी एक जरूरी हिस्सा है। दिन में दो बार ब्रश करें, रोज़ दांतों के बीच की सफाई करें, समय समय पर डेंटिस्ट को दिखाएं और अपने ब्लड शुगर को डॉक्टर की बताई रेंज में रखने की कोशिश करें। इससे आपके दांत और मसूड़े ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी सेहत भी बेहतर रह सकती है।

बच्चों की कम नींद बिगाड़ सकती है सेहत, सुधारें स्लीप रूटीन

आजकल कई बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसका असर उनकी सेहत और विकास पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं उम्र के हिसाब से बच्चों को कितनी नींद चाहिए और उनका स्लीप रूटीन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।

आजकल कई बच्चों की दिनचर्या पहले जैसी नहीं रही है। देर रात तक मोबाइल, टीवी या दूसरे स्क्रीन देखने, पढ़ाई का दबाव और गलत समय पर सोने की आदत की वजह से उनकी नींद प्रभावित हो रही है। कई बार माता-पिता इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक नींद पूरी न होने का असर बच्चों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। इसलिए बच्चों की नींद को लेकर शुरुआत से ही सावधानी बरतना जरूरी है।

बच्चों के अच्छे विकास के लिए पूरी नींद लेना उतना ही जरूरी है, जितना सही खाना और रोजाना शारीरिक एक्टिविटी करना।अच्छी नींद से शरीर को आराम मिलता है और दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है। वहीं, लगातार कम नींद लेने से बच्चा थका हुआ, चिड़चिड़ा या सुस्त महसूस कर सकता है। इससे पढ़ाई, खेलकूद और रोजमर्रा की एक्टिविटी पर भी असर पड़ सकता है। अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान दिया जाए, तो बच्चों का स्लीप रूटीन आसानी से सुधारा जा सकता है। आइए जानते हैं उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए कितनी नींद जरूरी है और उनका स्लीप रूटीन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।

उम्र के अनुसार बच्चों को कितनी नींद चाहिए?

अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक, बच्चों की उम्र के साथ उनकी नींद की जरूरत भी बदलती रहती है। नवजात शिशु (0 से 3 महीने) को हर दिन 14 से 17 घंटे की नींद की जरूरत होती है। 4 से 12 महीने के बच्चों के लिए 12 से 16 घंटे, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए 11 से 14 घंटे और 3 से 5 साल के बच्चों के लिए 10 से 13 घंटे की नींद जरूरी मानी जाती है।

वहीं, 6 से 12 साल के बच्चों को रोज 9 से 12 घंटे और 13 से 18 साल के टीनेजर बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। पर्याप्त नींद लेने से बच्चों का शरीर और दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। अगर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से पूरी नींद नहीं लेता, तो उसकी सेहत, पढ़ाई और रोजमर्रा की एक्टिविटी पर असर पड़ सकता है।

बच्चों का स्लीप रूटीन कैसे सुधारें?

बच्चों का स्लीप रूटीन सुधारने के लिए उन्हें रोज एक ही समय पर सुलाने और सुबह लगभग एक ही समय पर उठाने की आदत डालें। सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल, टीवी और टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें। बच्चे के कमरे का माहौल शांत और आरामदायक रखें, ताकि उसे आसानी से नींद आ सके। दिन में खेलकूद और शारीरिक एक्टिविटी के लिए समय जरूर दें। रात में बहुत भारी या ज्यादा मीठा खाना देने से बचें। सोने से पहले कहानी सुनाना या हल्का संगीत सुनाना भी बच्चे को आराम महसूस कराने में मदद कर सकता है।

कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है?

अगर बच्चा लंबे समय से ठीक से नहीं सो पा रहा है, रात में बार-बार जाग जाता है या दिनभर बहुत ज्यादा थका और सुस्त रहता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अगर सोते समय तेज खर्राटे आते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है या बच्चा नींद में बार-बार घबराकर उठ जाता है, तो भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में बच्चों के डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। सही समय पर इलाज और सलाह मिलने से बच्चे की नींद और उसकी सेहत, दोनों में सुधार हो सकता है।

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है शिया बटर लिप बाम

शिया बटर लिप बाम प्राकृतिक चीजों से बनाया जाता है। यह न केवल होंठों को नमी देता है, बल्कि उन्हें सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। शिया बटर में विटामिन-ए और विटामिन-ई होते हैं, जो होंठों को पोषण देते हैं और उन्हें मुलायम बनाते हैं। इस लेख में हम आपको घर पर शिया बटर लिप बाम बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने होंठों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं।

जरूरी चीजें

घर पर शिया बटर लिप बाम बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको शुद्ध शिया बटर, नारियल का तेल, बादाम का तेल और कुछ खुशबूदार तेल चाहिए होंगे।

इसके अलावा आपको एक साफ डिब्बा, एक छोटे चम्मच और एक माइक्रोवेव या चूल्हे की भी जरूरत पड़ेगी।

इन सभी चीजों को इक_ा करके आप शिया बटर लिप बाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

शिया बटर और नारियल का तेल मिलाएं

सबसे पहले एक छोटे बर्तन में शिया बटर और नारियल का तेल डालें और इसे धीमी आंच पर गर्म करें।

जब तक कि यह पूरी तरह से पिघल न जाए तब तक लगातार चलाते रहें। ध्यान रखें कि इसे अधिक गर्म न करें क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं।

जब मिश्रण पिघल जाए तो गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा, जिसमें विटामिन-ए और विटामिन-ई होंगे।

खुशबूदार तेल डालें

अब इस मिश्रण में अपने पसंदीदा खुशबूदार तेल डालें। आप लैवेंडर, पुदीना या नारियल आदि किसी भी प्रकार के खुशबूदार तेल का उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल लिप बाम को खुशबूदार बनाएगा बल्कि इसमें अतिरिक्त लाभ भी जोड़ देगा।

उदाहरण के लिए पुदीना तेल लगाने से होंठों पर ठंडक महसूस होगी और वे ताजगी भरे रहेंगे। इसके अलावा नारियल तेल लगाने से होंठ मुलायम और चमकदार बनेंगे।

मिश्रण को जमाएं

जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे साफ डिब्बे में डालें और कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें।

ठंडा होने पर आपका शिया बटर लिप बाम तैयार हो जाएगा, जिसे आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं।

यह लिप बाम आपके होंठों को प्राकृतिक रूप से पोषण देगा और उन्हें मुलायम बनाए रखेगा। इसे आप अपने हाथों में भी लगा सकते हैं ताकि आपकी त्वचा को नमी मिले।

कैसे करें इस्तेमाल?

आप इस लिप बाम का इस्तेमाल दिन में कई बार कर सकते हैं, खासकर जब आप बाहर हों या कहीं जा रहे हों।

इसे अपने होंठों पर लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें ताकि यह अच्छे से समा जाए। यह आपके होंठों को सूखेपन से बचाएगा और उन्हें नमी प्रदान करेगा।

इस प्रकार शिया बटर लिप बाम बनाने की प्रक्रिया सरल और फायदेमंद है, जिससे आप अपने पूरे परिवार के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

सावन के सोमवार पर रखना है व्रत, सेहत से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान

सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। इस पूरे महीने में कई श्रद्धालु हर सोमवार का व्रत रखते हैं। कुछ लोग दिनभर बिना अनाज के रहते हैं, तो कुछ केवल फलाहार करते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग पूरे श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करते हैं। हालांकि, व्रत रखने के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। लंबे समय तक खाली पेट रहने, कम पानी पीने या सही चीजें न खाने से शरीर में कमजोरी, चक्कर और थकान महसूस हो सकती है।

अगर सही खानपान और जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए, तो व्रत के दौरान शरीर को स्वस्थ रखना आसान हो सकता है। आइए जानते हैं सावन सोमवार का व्रत रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

व्रत रखने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, तो अपनी शारीरिक क्षमता को समझें। व्रत से एक दिन पहले रात का खाना समय पर खाएं और अच्छी नींद लें, ताकि शरीर को पर्याप्त आराम मिल सके। सुबह उठने के बाद पानी जरूर पिएं और अगर फलाहार करने वाले हैं, तो पौष्टिक चीजों का चुनाव करें। व्रत का मकसद केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को संतुलित रखना भी है। इसलिए अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें।

एनर्जी के लिए व्रत में क्या खाएं

व्रत के दौरान ऐसी चीजें खाएं, जो शरीर को लंबे समय तक एनर्जी दें। फल, दूध, दही, मखाना, मेवे, नारियल पानी और नींबू पानी अच्छे विकल्प हैं। अगर व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं, तो उससे बनी हल्की चीजें भी खाई जा सकती हैं। पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। बहुत ज्यादा तली-भुनी या मीठी चीजें खाने से बचें, क्योंकि इससे पेट भारी हो सकता है और थकान महसूस हो सकती है। संतुलित और हल्का भोजन व्रत के दौरान शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

व्रत रखने से पहले ये डॉक्टर की लें सलाह

अगर आपको डायबिटीज, हाई या लो ब्लड प्रेशर, किडनी, लिवर या दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। प्रेग्नेंट महिलाओं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं और बुजुर्गों को भी बिना सलाह के लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए। जो लोग रोजाना दवाएं लेते हैं, उन्हें यह भी पूछ लेना चाहिए कि दवा कब और कैसे लेनी है। अगर व्रत के दौरान चक्कर आए, बहुत कमजोरी महसूस हो या तबीयत बिगड़ने लगे, तो व्रत जारी रखने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

व्रत के दौरान कौन सी गलतियां सेहत पर पड़ सकती हैं भारी?

व्रत के दौरान कई लोग पूरे दिन बहुत कम पानी पीते हैं या सिर्फ चाय और कॉफी के सहारे रहते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। कुछ लोग शाम को एक साथ बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिससे पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तली-भुनी और बहुत मीठी चीजें ज्यादा खाने से भी बचना चाहिए। अगर व्रत के दौरान लगातार चक्कर आए, कमजोरी बढ़े या घबराहट महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में शरीर की जरूरत को समझें और जरूरत पड़ने पर व्रत तोड़ने में संकोच न करें।

सिर्फ नंबर मास्क करने से सेफ हो जाएगा UPI डेटा? क्यों अधूरा है प्राइवेसी का ये सॉल्यूशन

DPDP फ्रेमवर्क के तहत, मोबाइल नंबर या पूरी पहचान ज़ाहिर करने से बड़ी ज़िम्मेदारी या जोखिम पैदा होता है, इसलिए NPCI प्राइवेसी को बेहतर बनाने के लिए UPI ऐप्स और बैंकों से सलाह-मशविरा कर रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इसको लेकर किस तरह का अपडेट सामने आया है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ग्राहकों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून को लागू करने के बारे में UPI ऐप्स और पार्टनर बैंकों के साथ बातचीत कर रही है। NPCI, जो देश का सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म UPI चलाती है, ने पहले ही फोन नंबरों को मास्क करने (छिपाने) का आदेश दे दिया है। UPI इकोसिस्टम पेमेंट करने और उन्हें वेरिफाई करने के लिए फोन नंबरों पर निर्भर करता है, जो एक ही समय में एक सिक्योरिटी फीचर और प्राइवेसी के लिए जोखिम भी है।

एक UPI ऐप के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने नाम न बताने की शर्त पर मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में कहा कि हालांकि, DPDP लागू होने का मतलब होगा कि फोन नंबर या पूरे नाम प्राइवेसी के लिए जोखिम हो सकते हैं, और NPCI बैंकों और UPI ऐप्स से बात कर रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि उनके सिस्टम हर भागीदार की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें ठीक करने के लिए तैयार हैं।

फोन नंबर मास्क किए जाएंगे

पिछले महीने, NPCI ने पेमेंट ऐप्स को ग्राहकों के फोन नंबर मास्क करने के लिए एक सर्कुलर भेजा था ताकि प्राइवेसी की सुरक्षा और सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि महिला यूजर्स की ओर से सोशल मीडिया पर कई शिकायतों में पहचान, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। NPCI ने इस आदेश को लागू करने के लिए 4 सितंबर की डेडलाइन तय की है।

NPCI ने कहा कि UPI मेंबर बैंकों और UPI ऐप्स को यूजर की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। यूजर्स की जानकारी, जैसे UPI ID, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर, UPI मेंबर बैंकों और UPI ऐप्स के सभी कस्टमर-फेसिंग इंटरफेस और कम्युनिकेशन में मास्क की जानी चाहिए।

यूजरनेम-बेस्ड UPI ID

दूसरे पक्ष को कस्टमर के मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखने चाहिए। QR कोड के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन के लिए, पेमेंट होने के बाद ऐप को मोबाइल नंबर नहीं दिखाना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि UPI ऐप्स को यूजर्स को मोबाइल नंबर पर आधारित ID के अलावा दूसरी ID रखने और उसे अपनी डिफॉल्ट ID के तौर पर सेट करने की सुविधा देनी चाहिए।

जब ग्राहक पहली बार UPI के लिए साइन अप करते हैं, तो ज्यादातर यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को ही अपना वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस (VPA) चुनते हैं। UPI में हमेशा से ही इसके बजाय यूजरनेम चुनने का विकल्प रहा है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स इस विकल्प के बारे में नहीं जानते हैं। इस सर्कुलर के साथ, मोबाइल नंबर के बजाय यूजरनेम डिफॉल्ट होगा, जिससे प्राइवेसी बेहतर होगी।

पीवीसी आयात पर सरकारी पहरा, क्या फिर बिगड़ने वाला है आपके घर का बजट?

जल्द ही घर बनाना और भी महंगा होने वाला है। खेती के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाना या घर की वायरिंग कराना आम आदमी के बजट को बढ़ाने वाला है। सरकार ने सस्ते विदेशी प्लास्टिक कच्चे माल पर नकेल कसने का फैसला किया है। लेकिन इस नीतिगत फैसले का सीधा झटका आम जनता की जेब पर लगने वाला है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने हाल ही में सस्पेंशन - ग्रेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (एस-पीवीसी) रेजिन के आयात नियमों को सख्त कर दिया है। यह एक तरह का प्लास्टिक कच्चा माल है, जिसका इस्तेमाल घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी के पाइप, बिजली के तारों की कोटिंग, खिड़कियों की फ्रेम, प्लास्टिक पैकिंग, कई चिकित्सा उत्पादों और यहां तक कि जूतों के सोल बनाने में होता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एस- पीवीसी रेजिन पर न्यूनतम आयात मूल्य 0.76 डॉलर (लगभग 64 रुपये) प्रति किलोग्राम या उससे कम कीमत वाले आयात के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस कदम से घरेलू पीवीसी रेजिन की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1.63 अरब डॉलर का रेजिन आयात किया था। चीन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, इसके बाद जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, थाइलैंड, अमेरिका, सिंगापुर एवं वियतनाम का स्थान रहा। जीटीआरआई के मुताबिक, इन देशों से आयात की औसत कीमत 0.65 डॉलर से 0.75 डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच रही, जो डीजीएफटी की तय राशि 0.76 डॉलर से कम है। ऐसे में मौजूदा आयात का बड़ा हिस्सा अब अंकुश के दायरे में आ जाएगा।

घर से लेकर खेत तक दिखेगा असर

घर बनाने में पीवीसी पाइप, फिटिंग और बिजली के तारों की बड़ी खपत होती है। जब कच्चा माल महंगा होगा, तो कंपनियां इसका बोझ सीधे ग्राहकों पर डालेंगी। खेती- किसानी और पानी की पाइपलाइनों में 70 से 80 फीसदी पीवीसी का इस्तेमाल होता है। पाइप महंगे होने से किसानों का बजट बिगड़ेगा। इस कच्चे माल का इस्तेमाल पैकेजिंग फिल्मों और आम जूतों-चप्पलों में भी होता है, जिससे दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं महंगी हो सकती हैं।

छोटे उद्योगों के लिए बड़ा खतरा

भारत में पीवीसी पाइप और केवल बनाने वाली हजारों छोटी और मझोली इकाइयां हैं। सस्ता माल न मिलने से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इसका असर दोतरफा होगा, या तो उत्पाद महंगे होंगे, या फिर कई छोटी इकाइयां बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। देश कुल जरूरत का 64 फीसदी एस-पीवीसी रेजिन आयात करता है।

'हमास से हथियार छोड़ने पर बनी सहमति' : डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

वॉशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गाजा में जारी युद्ध को रोकने के लिए एक बड़ा समझौता हो गया है। उनके 'बोर्ड ऑफ पीस'ने गाजा में हमास और अन्य सभी हथियारबंद समूह के 'पूर्ण निशस्त्रीकरण' पर सहमति बना ली है। ट्रंप ने इसे शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह समझौता एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा। ट्रंप के अनुसार, जैसे-जैसे गाजा में निशस्त्रीकरण का काम पूरा होता जाएगा, वैसे-वैसे इजरायली सेना पीछे हटती जाएगी। इसके बाद 'इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स' वहां की कमान संभालेगी। यह फोर्स नई फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गाजा को सुरक्षित बनाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में 200 से 300 दिनों का समय लग सकता है।

मामले से जुड़ी पांच बड़ी बातें

हथियार सौंपेगा हमासः हमास और अन्य सभी गुट अपने हथियार डालेंगे और सुरंगे नष्ट करेंगे।

इस्राइली सेना की वापसीः निशस्त्रीकरण पूरा होने के साथ ही इजरायली सेना गाजा छोड़ देगी।

नई सुरक्षा व्यवस्थाः अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल (आईएसएफ) और नई फलस्तीनी पुलिस गाजा की सुरक्षा संभालेगी।

नई फलस्तीनी सरकारः गाजा का शासन एक नई सिविल सरकार चलाएगी, जो बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करेगी।

3 देशों की बड़ी भूमिकाः मिस्र, कतर और तुर्की की मध्यस्थता से यह समझौता संभव हुआ है।

'ढह चुका है पाकिस्तान का सिस्टम': गृह मंत्री मोहसिन नकवी का कबूलनामा; क्यों कही यह बात?

वॉशिंगटन, एजेंसी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की बदहाल स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अब यह देश की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। इस्लामाबाद में आयोजित पहले 'पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट' को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, वह ढह चुकी है। मानो या न मानो आप इस व्यवस्था को 70 साल से घसीट रहे हैं, और जबकि हम सब लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र के अंदर कई रूप होते हैं। मौजूदा व्यवस्था के जरिए समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। "

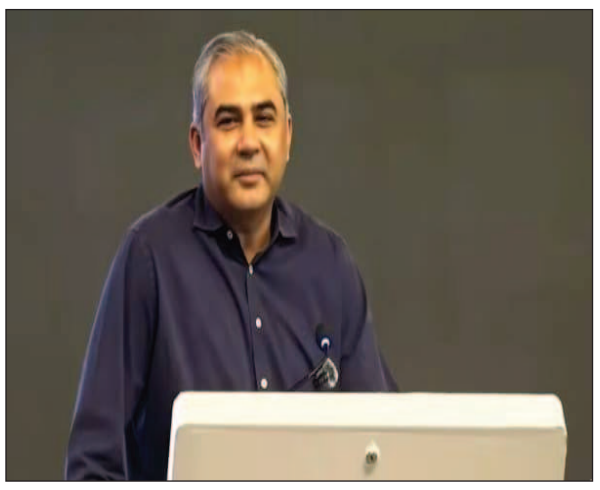

गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधारों की वकालत की है। उन्होंने नए प्रशासनिक निकायों और नई इकाइयों के गठन पर जोर दिया। नकवी की यह मांग पाकिस्तान के कई प्रमुख राजनीतिक दलों की उस पुरानी मांग से मेल खाती है, जिसमें बेहतर शासन संचालन के लिए देश में अधिक प्रांत बनाने की बात कही जाती रही है। नकवी के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व भी अब यह मानने लगा है कि मौजूदा ढर्रे पर देश को आगे चलाना नामुमकिन है।

रिकॉर्ड कर्ज का बोझ और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट

पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक दौर से गुजर रहा है। देश का कुल विदेशी कर्ज लगभग 137 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, जिसमें आईएमएफ का ही 8.8 अरब डॉलर है। यह कुल सरकारी कर्ज जीडीपी का करीब 70% से 80% तक पहुंच गया है। हालत यह है कि पाकिस्तान सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा (लगभग दो-तिहाई) केवल पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम बचा है कि वह बिना किसी बाहरी वित्तीय मदद के कुछ महीनों का आयात भी नहीं संभाल सकता।

IMF और मित्र देशों पर पूरी निर्भरता

पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर से बाहर निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाने के लिए मजबूर है। आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान 25 बार आईएमएफ से बेलआउट पैकेज (कर्ज) ले चुका है। आईएमएफ की सख्त शर्तों (जैसे टैक्स बढ़ाना, बिजली-ईंधन के दाम बढ़ाना और सब्सिडी खत्म करना) के कारण देश में आम जनता भारी महंगाई झेल रही है। इसके अलावा, सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मित्र देशों से बार-बार रोलोवर (पुराने कर्ज की मियाद बढ़ाना) और नकद जमा मांगकर देश का कामकाज चलाया जा रहा है।

प्रशासनिक नाकामी और ढांचागत बदहाली

गृह मंत्री नकवी के बयान का दूसरा पहलू प्रशासनिक नाकामी से जुड़ा है। 70 साल पुराना केंद्रीय ढांचा न तो सही तरीके से टैक्स वसूल पा रहा है और ना ही सुरक्षा व बुनियादी सुविधाएं दे पा रहा है। देश का कर-से-जीडीपी अनुपात मात्र 10-11% के आसपास अटका हुआ है। भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, और संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण शासन व्यवस्था चरमरा गई है। इसी वजह से राजनीतिक स्तर पर छोटे प्रशासनिक ब्लॉक और नए प्रांत बनाने की मांग उठ रही है ताकि शासन को सही तरीके से चलाया जा सके।

मोरक्को की सीमा तोड़कर स्पेन में घुसे हजारों प्रवासी: नौ की मौत, मचा हड़कंप; यूरोप के सामने खड़ा हुआ नया संकट?

स्यूटा। मोरक्को से हजारों प्रवासी गुरुवार को स्पेन के छोटे से स्वायत्त क्षेत्र स्यूटा में पहुंच गए। सीमा पार करते समय मची अफरा-तफरी में नौ लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने स्पेन सरकार से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और सीमा पर स्थिति संभालने के लिए सेना भेजने की मांग की। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा और देश की सीमा की रक्षा सुनिश्चित करेगा। हालांकि, सरकार प्रवास से जुड़ी चिंताओं को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकती।

राशिद सबीही स्यूटा में स्पेन की सिविल गार्ड के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह अराजक है। उन्होंने कहा, सटीक संख्या बताना संभव नहीं है,

लेकिन हजारों प्रवासी सीमा पार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है।

उत्तरी मोरक्को में मानवाधिकार संगठन के सदस्य अशरफ मैमौनी ने स्थिति को 'असाधारण' बताया। उन्होंने कहा, आज सुबह ताराजल सीमा को असामान्य हालात में खोला गया और लोग वहां से अंदर आ गए।

वीडियो फुटेज में दिखाया गया कि बड़ी संख्या में लोग ताराजल समुद्र तट के किनारे बने तटबंधों से होते हुए स्थानीय सड़कों पर पहुंच रहे थे। इनमें ज्यादातर मोरक्को के नागरिक थे। ज्यादातर युवा पुरुष दिखाई दे रहे थे, लेकिन महिलाओं और बच्चों वाले परिवार भी शामिल थे। कुछ लोगों ने एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम कर रहे एक स्वतंत्र फोटोग्राफर को देखकर 'विवा एस्पाना' (स्पेन जिंदाबाद) के नारे भी लगाए। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों के स्यूटा पहुंचने की वजह क्या थी।

स्पेन-मोरक्को सीमा पर क्यों बढ़ा संकट?

स्पेन और मोरक्को की सीमा पर यह तनाव बुधवार को छोटे से स्पेनिश क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की संख्या बढ़ने के बाद बढ़ा। इनमें से ज्यादातर लोग समुद्र में तैरकर स्यूटा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सबीही और मोरक्को तथा स्यूटा के सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, बुधवार को समुद्र के रास्ते स्यूटा पहुंचने की कोशिश में तीन लोगों की मौत हो गई। मोरक्को के अधिकारियों ने इस सीमा पार करने की घटना पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि मोरक्को सरकार स्थिति संभालने में स्पेन के साथ 'करीबी सहयोग' कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि मोरक्को की पुलिस सीमा पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रोक रही है। दोनों देशों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई है, ताकि स्यूटा में अवैध रूप से दाखिल हुए सभी लोगों को जल्द से जल्द वापस भेजा जा सके। स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे-मार्लास्का शुक्रवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए स्यूटा जाएंगे। स्यूटा के अधिकारियों ने पहले प्रवासियों की बढ़ती संख्या को इस महीने की शुरुआत में आए स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ा था। इस फैसले के तहत समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचने वाले प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। हालांकि, जमीन के रास्ते सीमा पार करने वालों पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे, सीमा पर लगी बाड़ को पार करके आने वाले लोगों को अलग नियमों के तहत रोका जाता है। हालांकि, मोरक्को के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को प्रवासियों की बढ़ती संख्या की वजह मानने पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि ज्यादातर प्रवासियों को ऐसे कानूनी फैसलों की जानकारी भी नहीं होगी। बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश या अपने देशों में हिंसा से बचने के लिए यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए स्पेन एक प्रमुख प्रवेश मार्ग है।

उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित स्यूटा पहुंचने के लिए प्रवासी अक्सर मोरक्को के फनीदेक शहर से तैरकर आते हैं। उन्हें करीब 3.1 मील यानी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कुछ लोग पास के बेलेयुनेक शहर से भी सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, जहां दूरी कम है। सीमा पार करते लोगों के ये दृश्य मई 2021 के उस संकट की याद दिलाते हैं, जब सिर्फ दो दिनों में 8,000 से ज्यादा प्रवासी स्यूटा में पहुंच गए थे। उस समय मोरक्को पर आरोप लगा था कि उसने सीमा पर निगरानी ढीली कर दी और प्रवासियों को स्यूटा में प्रवेश करने दिया। यह घटना तब हुई थी, जब स्पेन ने मोरक्को के प्रतिद्वंद्वी संगठन पोलिसारियो फ्रंट के नेता ब्राहिम गाली को इलाज के लिए स्पेन के एक अस्पताल में आने की अनुमति दी थी। इससे रबात और मैड्रिड के बीच कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।

पोलिसारियो फ्रंट दशकों से पश्चिमी सहारा के लोगों का प्रतिनिधि होने का दावा करता रहा है और इस क्षेत्र को स्वतंत्र कराने की मांग करता है। पश्चिमी सहारा को लेकर मोरक्को और इस संगठन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है।

स्यूटा के प्रमुख ने की सेना तैनात करने की मांग

स्यूटा की क्षेत्रीय सरकार के प्रमुख जुआन जीसस विवास ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्पेन की केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की मांग की। उन्होंने सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल और सेना तैनात करने की अपील की। विवास ने कहा कि सीमा की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस और सैनिकों की जरूरत है। उन्होंने बुधवार को चेतावनी दी थी कि प्रवासियों को रखने वाले केंद्रों पर दबाव बढ़ गया है। पिछले सप्ताह 1,500 से अधिक प्रवासी स्यूटा पहुंच गए थे, जिसके बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर सो रहे थे। लेकिन बुधवार रात और गुरुवार को हजारों और लोग सीमा पार कर गए।

पीएम मोदी के एडिटेड वीडियो मामले में एक्शन, मेटा इंडिया हेड के खिलाफ हैदराबाद में FIR दर्ज

नई दिल्ली, एजेंसी। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने पीएम मोदी के खिलाफ एडिट किए गए आपत्तिजनक वीडियो के मामले में केस दर्ज किया है। हैदराबाद पुलिस ने Meta के इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास और कई फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया है।

दरअसल, एआई (AI) द्वारा तैयार की गई आपत्तिजनक सामग्री से सामाजिक शांति बिगड़ने का आरोप लगाते हुए तेलंगाना के दो निवासियों की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। जिन्होंने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम ब्राउज करते समय, उन्हें कई मॉर्फ्ड और डिजिटल रूप से हेरफेर किए गए, कई वीडियो और छवियां मिलीं, जिनमें प्रधानमंत्री को अश्लील, अपमानजनक और गुमराह करने वाले तरीके से चित्रित किया गया था।

विवाद के बाद मेटा ने भारत सरकार को पत्र लिखकर वीआईपी अकाउंट्स की निगरानी बढ़ाने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कंटेंट की जांच कराने का भरोसा दिया है।

पुलिस ने दर्ज किए दो मामले

ये शिकायतें 29 वर्षीय व्यवसायी एस अरविंद रेड्डी और तेलंगाना भाजपा कार्यकर्ता टी साईकिरण गौड़ ने दर्ज कराई हैं। जिसके बाद पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैंडलर्स को आरोपी बनाया है, जबकि मेटा के इंडिया हेड को दोनों मामलों में सह-आरोपी के रूप में नामजद किया है।

हैदराबाद पुलिस को की शिकायत में आरोप लगाया गया है, 'प्रधानमंत्री और हेरफेर की गई सामग्री में दिखाए गए अन्य व्यक्तियों के प्रति आपत्तिजनक भाषा, उपहास और अभद्र टिप्पणियां शामिल हैं, जिससे पोस्ट की आपत्तिजनक प्रकृति और बढ़ जाती है और उनका व्यापक प्रसार और सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त सामग्री को डिजिटल रूप से एडिट किया गया है या एआई द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है।

मेटा ने दिया भरोसा

मेटा ने PM मोदी सहित प्रमुख खातों के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाते हुए सरकार को आश्वस्त किया है। अब ऐसे VIP पदों की जांच और समीक्षा मेटा के सीनियर अधिकारी ही करेंगे। सामग्री विनियमन (कंटेंट रेगुलेशन) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए मेटा की टीम इस सप्ताह सरकार से मुलाकात करेगी।

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शनों और 20 जुलाई के 'संसद चलो' मार्च के दौरान PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक व अपमानजनक पोस्ट अपलोड करने पर दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट हटाने का निर्देश देने के साथ-साथ कई न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को नोटिस जारी किए हैं।

उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, जमानत के लिए दायर की है अर्जी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले के आरोपी उमर खालिद की रेगुलर जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत अर्जी पर भी नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को करेगा। 27 अगस्त को दंगों मामले में सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

उमर खालिद की जमानत अर्जी तीन बार खारिज हो चुकी है। 4 जुलाई को निचली अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं, कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने

UAPA मामलों में जमानत के सवाल को एक बड़ी बेंच के पास भेजा है।

खालिद की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की गई है। यह अर्जी तब तक के लिए है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर फैसला नहीं कर लेता कि क्या लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी के कारण UAPA जैसे कानूनों में जमानत पर लगी पाबंदियों को दरकिनार किया जा सकता है। दो बेंचों की अलग-अलग राय के बाद इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजा गया है।

'ये ट्रायल कोर्ट की गलती'

हाई कोर्ट में अपनी अपील में खालिद ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार करके 'गलती' की। ट्रायल कोर्ट ने उनकी नई जमानत अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसी तरह के आधारों पर उनकी अर्जियां खारिज कर चुका है। खालिद ने ट्रायल कोर्ट में यह नई अर्जी तब दायर की थी, जब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 18 मई को पिछली बेंच के उस फैसले पर सवाल उठाए थे, जिसमें 5 जनवरी को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा?

उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा "कोई विकल्प नहीं" था और इसलिए, "वह न तो याचिकाओं पर विचार कर सकती थी और न ही उन्हें राहत दे सकती थी।"

टॉम हॉलैंड का चला जादू, 'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे' पर यूजर्स बोले- बेहतरीन फिल्म

मार्वल स्टूडियो की 'स्पाइडर मैन' फ्रैंचाइजी की फिल्मों की दुनिया भर में अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। आज सिनेमाघरों में 'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे' रिलीज हुई। अब सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जानिए, फिल्म 'स्पाइडर मैन- ब्रांड न्यू डे' फैंस को कैसी लगी।

एक फैन ने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर फिल्म देखने के बाद कमेंट लिखा, 'कई आलोचकों का कहना है कि 'स्पाइडर-मैनः ब्रांड न्यू डे', 'स्पाइडर-मैन 2' के बाद आई सबसे बेहतरीन स्पाइडर-मैन फिल्म है।' इसी तरह एक फैन ने कमेंट में लिखा, 'यह फिल्म मेरी पसंदीदा स्पाइडर-मैन फिल्म है। यह सच में जबरदस्त है। यह बहुत शानदार दिखती है। इसकी कहानी बहुत बढ़िया है। सभी की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। मैं पूरी फिल्म के दौरान मुस्कुराता रहा।

एक फैन ने रिएक्शन देते हुए लिखा, 'मुझे इस फिल्म का हर पल बहुत पसंद आया। एक बेहतरीन और मैच्योर कैरेक्टर स्टडी, जिसे बहुत ही रोमांचक तरीके से शूट किया गया है। कई चीजों को बैलेंस करने के बावजूद इसका फिनाले बहुत ही संतोषजनक रहा और इसने मुझे रुला दिया। यह अब तक की सबसे बेहतरीन और असली स्पाइडर-मैन फिल्म है। मैं अभी बहुत खुश हूं।'

यह फिल्म फैंस के लिए ट्रिब्यूट है

कुछ यूजर्स ने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर 'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे' को फैंस के लिए ट्रिब्यूट बताया। एक यूजर ने लिखा, 'फैंस के लिए एक असली ट्रिब्यूट जैसा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे किसी तरह पहले ही देख लिया है। जैसे यह कई साल से मेरे दिमाग में घूम रही हो।'

वहीं एक फैन ने लिखा, 'अभी-अभी फिल्म 'स्पाइडर-मैनः ब्रांड न्यू डे' देखी। यह एकदम परफेक्ट नहीं है, थोड़ी ज्यादा लंबी है। लेकिन फिल्म में सभी कहानियां जिस तरह से एक साथ जुड़ती हैं, वह बहुत ही शानदार है। कई बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। विज़ुअली यह मार्वल की सबसे अच्छी स्पाइडर-मैन फिल्म है और सबसे ज्यादा इमोशनल भी।' फिल्म में टॉम हॉलैंड, जेंडाया के अभिनय की भी फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म के विचुएल, एक्शन की भी जमकर तारीफ सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं।

'वाराणसी' की शूटिंग के बीच प्रियंका चोपड़ा ने निकाला वक्त, इस काम के लिए पति और साथी कलाकार के साथ निकलीं बाहर

प्रियंका चोपड़ा ने 'वाराणसी' की शूटिंग के बीच अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है। वह अपने पति और अपने साथी कलाकार के साथ नजर आईं हैं।

प्रियंका चोपड़ा अभी हैदराबाद में एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग कर रही हैं। उनके साथ उनके पति निक जोनस और बेटी मालती भी हैं। शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल के बीच, प्रियंका अपने पति निक और अपने को-स्टार महेश बाबू के साथ मूवी नाइट के लिए बाहर आईं।

निक जोनस और महेश बाबू के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा अपने साथी कलाकार महेश बाबू और पति निक जोनस के साथ एक सिनेमाघर के बाहर पोज देते हुए दिख रही हैं। प्रियंका ने आइवरी रंग का स्लीवलेस ड्रेस पहना है। उन्होंने ओवरसाइज सनग्लासेस और खुले बालों से अपने लुक को पूरा किया है। निक ने सफेद वेस्ट के ऊपर टेक्सचर शर्ट पहनी। वहीं महेश बाबू कैजुअल लुक में थे।

कब रिलीज होगी 'वाराणसी'?

फिल्म 'वाराणसी' में प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन हैं। यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 1200 से 1400 करोड़ रुपये के बीच है।

कीर्ति कुल्हारी हुईं साइबर फ्रॉड का शिकार, लाखों की ठगी के बाद पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत

: बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी के साथ साइबर ठगी हुई। फ्रॉड करने वालों ने लाखों रुपये उनके क्रेडिट कार्ड से चुरा लिए। कीर्ति कुल्हारी ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी के साथ साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अज्ञात अपराधियों ने उनके मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड का अनधिकृत एक्सेस हासिल कर महज कुछ ही मिनटों में 2,43,852 रुपए का फ्रॉड किया है। अभिनेत्री की शिकायत पर अंबोली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आईएएनएस की खबर के मुताबिक इस मामले में कीर्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में बताया गया है कि कीर्ति के साथ साइबर ठगी रात के समय लगभग 9:31 बजे हुई थी। उस समय वह अंधेरी पश्चिम में फन रिपब्लिक मॉल के पास स्थित सिनेपोलिस थिएटर में थीं। इसी दौरान उनके मोबाइल नंबर पर बैंक के क्रेडिट कार्ड से एयरोमेक्सिको एयरलाइन पर 2,525 अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अलर्ट मैसेज मिला।

अनजान और संदिग्ध विदेशी लेनदेन का मैसेज देखते ही अभिनेत्री ने बिना समय गंवाए बैंक के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया। बैंक अधिकारियों ने जांच के बाद बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड से बिना अनुमति के चार अलग-अलग बड़े ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा के तौर पर तुरंत कार्ड ब्लॉक कर दिया गया।

अभिनेत्री का क्रेडिट कार्ड हैक किया गया था

अभिनेत्री ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड पूरी तरह गोपनीय था, जिसे उन्होंने किसी के साथ साझा नहीं किया था। आशंका जताई जा रही है कि किसी डिजिटल मालवेयर या स्पाईवेयर के जरिए उनका फोन और कार्ड हैक किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अंबोली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की टीम बैंक रेफरेंस नंबरों और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

इन फिल्मों के कारण चर्चा में रहीं कीर्ति कुल्हारी

कीर्ति कुल्हारी के करियर फ्रंट की बात करें तो उन्होंने 'पिंक', 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक', 'इंदु सरकार', 'मिशन मंगल' और 'क्रिमिनल जस्टिस' जैसी हिट फिल्मों में जबरदस्त अभिनय किया है। हाल ही में वह एक सीरीज 'शेखर होम' में नजर आई थीं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com